EDU TERIA

E - D.N.A

Daily Newspaper Analysis

Prelims Mains Essay

By- Nikhil Ranjan

Useful For Prelims

Date: 02 January 2026

कारगिल युद्ध के अमर नायकों में शामिल हैं बलिदानी मेजर विवेक गुप्ता

मेजर विवेक गुप्ता का जन्म 1970 में आज ही देहरादून में हुआ था। 1992 में राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट की द्वितीय राज राइफल बटालियन में शामिल हुए। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उन्हें द्रास सेक्टर में तोलोलिंग चोटी पर स्थित शत्रु चौकियों पर फिर से कब्जा करने का मिशन सौंपा गया। 13 जून को भारी गोलीबारी के बीच उनके नेतृत्व में कंपनी दुश्मन के करीब पहुंचने में सफल रही। चौकी पर पहुंचकर उन्होंने आमने-सामने की लड़ाई में तीन शत्रु सैनिकों को मार गिराया और चौकी पर कब्जा किया। इस दौरान वह स्वयं भी बलिदान हो गए। मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र मिला।

Dainik Jagaran Page No-14

डब्ल्यूएचओ ने गेमिंग की लत को घोषित किया मानसिक विकार

2018 में आज ही डब्ल्यूएचओ ने गेमिंग डिसआर्डर को एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के रूप में मान्यता दी थी। इसमें गेमिंग पर नियंत्रण खो जाना, अन्य गतिविधियों की तुलना में गेमिंग को प्राथमिकता देना और नकारात्मक परिणामों के बावजूद गेमिंग जारी रखना शामिल है।

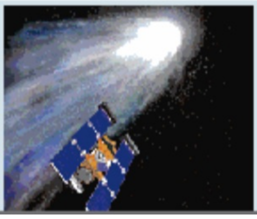

स्टार्डस्ट अंतरिक्ष यान ने धूमकेतु की धूल का नमूना किया एकत्र

2004 में आज ही नासा के स्टारडस्ट अंतरिक्ष यान ने धूमकेतु वाइल्ड-2 से धूल के नमूने एकत्र किए। 2006 में नमूना युक्त कैप्सूल पृथ्वी पर लौटा। यह पहली बार था जब धूमकेतु की सामग्री को पृथ्वी पर लाया गया। इससे सौर मंडल के निर्माण को लेकर समझ बढ़ी।

Dainik Jagaran Page No-14

राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की रपट में जताई गई चिंता | वन्यजीव | 2024 की तुलना में 40 अधिक, मध्यप्रदेश में सबसे अधिक मृत पाए गए बाघ

दिसंबर में हर दूसरे दिन एक बाघ की मौत, 2025 में 166 मरे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जनवरी।

साल का आखिरी माह देश के बाघों पर भारी पड़ा है। माह में हर दो दिन में एक बाघ की मौत हुई है। दिसंबर में कुल 15 बाघ मरे हैं। यह आंकड़ें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की रपट में सामने आए हैं। वर्ष 2024 में 126 बाघों की मौत हुई थी, वहीं 2025 में 166 बाघों की मौत हुई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 40 अधिक हैं।

दिसंबर 2025 में बाघों की मौत का आंकड़ा बताता है कि जो भी बाघ मरे पाए गए हैं। उन बाघों में छह बाघ अभयारण्य क्षेत्र में ही मरे पाए गए हैं जबकि बाकी बाघ संरक्षित क्षेत्र के दायरे से बाहर थे। दिसंबर में जिन बाघों के मृत पाए जाने का आंकड़ा सामने आया है। उन बाघों में दो मादा और तीन बच्चे समेत अन्य व्यस्क बाघ शामिल पाए गए हैं। जिन राज्यों से ये मामले सामने आए हैं। उन राज्यों में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ राज्य के वन्य अभयारण्य क्षेत्र शामिल हैं। सबसे अधिक बाघों की मौत के मामले मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए हैं।

दिसंबर 2025 में बाघों की मौत का आंकड़ा बताता है कि जो भी बाघ मरे पाए गए हैं। उन बाघों में छह बाघ अभयारण्य क्षेत्र में ही मरे पाए गए हैं जबकि बाकी बाघ संरक्षित क्षेत्र के दायरे से बाहर थे। दिसंबर में जिन बाघों के मृत पाए जाने का आंकड़ा सामने आया है। उन बाघों में दो मादा और तीन बच्चे समेत अन्य व्यस्क बाघ शामिल पाए गए हैं।

केंद्र सरकार बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए चलाए गई एक विशेष मुहिम के तहत इन बाघों एनटीसीए के माध्यम से निगरानी रखती है जिससे इनकी आबादी को विस्तार मिल सके। बताया जा रहा है कि इन बाघों के लिए अभ्यारण्य क्षेत्र में दो से तीन स्तर के बाड़ों का घेरा होता है। इस घेरे को भी तोड़कर बाघ बाहर चले जाते हैं।

इस वजह से सुरक्षा घेरे के बाहर ही ज्यादा बाघों की मौत के मामले सामने आते हैं। इस तरह के जितने भी मामले सामने आते हैं। उन मामलों की फारेंसिक जांच कराई जाती है। सरकार एजंसियों देशभर के अभयारण्य क्षेत्र में कैमरे और बाघों के फुट प्रिंट के आधार पर निगरानी रखती है।

आंकड़ों में अभी संबंधित एजंसियों के पास वर्ष 2012-24 तक मौतों के आंकड़े की रपट है। रपट बताती है कि इन मामलों में 71 फीसद मामलों को जांच के बाद बंद किया जा चुका है और अभी भी 29 फीसद मामले लंबित हैं। केंद्र सरकार ने बाघों की स्थिति को जांचने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी।

वर्ष 2022 में बाघों की एक गणना रपट भी सरकारी एजंसियों ने जारी की थी इसके मुताबिक देश में कुल बाघों की संख्या 3682 होने का दावा किया गया है। इस आधार पर सरकारी एजंसियों ने दावा किया गया था कि वर्ष 2018 में यह संख्या 2967 थी, जो कि इनकी संख्या में 24 फीसद की बढ़ोत्तरी है। इसी रपट में केंद्र सरकार ने दुनिया में बाघों की 75 फीसद आबादी को भारत के वन क्षेत्र का पहली पसंद होने का दावा किया था।

Jansatta Page No-10

'वसुधैव कुटुंबकम' के हिमायती समाज में पारिवारिक विवाद विडंबनापूर्ण : हाई कोर्ट

मुंबई, प्रेट्र : बांबे हाई कोर्ट ने समाज की इस विडंबना पर दुख जताया है जो दुनियाभर में "वसुधैव कुटुंबकम" की हिमायत करता है और उसके अपने ही घरों में विरासत को लेकर झगड़े होते हैं। संपत्ति के अंतहीन विवादों को प्राचीन मूल्यों व आधुनिक वास्तविकता के बीच जुड़ाव की कमी का उदाहरण बताते हुए कोर्ट ने उम्मीद जताई कि समाज के हित में कटु व लंबे समय तक चलने वाले पारिवारिक मुकदमों में कमी आएगी।

जस्टिस एमएस सोनक और अद्वैत सेठना की पीठ ने इस हफ्ते की शुरुआत में दिए फैसले में उस बेटी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसने दिवंगत मां की वसीयत के संबंध में लेटर आफ एडमिनिस्ट्रेशन (संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार पत्र) जारी करने की मांग की थी, जिसमें उपनगरीय बांद्रा में परिवार की संपत्ति उसे और उसके दो भाइयों को

उम्मीद जताई, समाज के व्यापक हित में लंबे और कटु पारिवारिक मुकदमों में आएगी कमी

पिता की वसीयत के विरुद्ध मां की वसीयत लागू करने की एक बेटी की याचिका खारिज की

दी गई थी। दो अन्य भाइयों, जिन्हें वसीयत से बाहर रखा गया था, ने अपनी मां की वसीयत पर संदेह जताया था और दावा किया था कि यह प्रभाव डालकर व मिलीभगत से बनाई गई थी। इन दोनों भाइयों को मां की वसीयत से पहले बनी पिता की वसीयत में संपत्ति के एक्जीक्यूटर के रूप में नामित किया गया था। कोर्ट ने मां की वसीयत के संबंध में लेटर आफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी करने से इन्कार करते हुए कहा, इस वसीयत के संबंध में संदिग्ध व संदेहास्पद परिस्थितियां मौजूद हैं।

याचिका के मुताबिक, अपीलकर्ता के माता-पिता की शादी 1933 में हुई थी और उनके छह बच्चे (पांच बेटे व एक बेटी) थे। 1976 में अपीलकर्ता के पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने वसीयत में अपनी पत्नी व दो बेटों को संपत्ति का एक्जीक्यूटर एवं ट्रस्टी बनाया था। 1987 में मां की मृत्यु हो गई। उन्होंने वसीयत छोड़ी जिसमें अपनी संपत्ति अपनी बेटी व दो अन्य बेटों को दी। जिन दो बेटों को शुरू में पिता की वसीयत में ट्रस्टी बनाया गया था, उन्होंने दावा किया कि उनकी मां की वसीयत अस्पष्ट थी और उसमें यह नहीं बताया गया था कि उन्हें वसीयत से क्यों बाहर रखा गया।

Jansatta Page No-13

देश में 15 अगस्त 2027 से दौड़ने लगेगी बुलेट ट्रेन, मंत्री बोले- अभी से खरीद लीजिए टिकट

नई दिल्ली, आइएएनएसः देश में बुलेट ट्रेन चलाने का सपना जल्द पूरा होने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए साल के पहले दिन देशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी है। इसकी तारीख की घोषणा करते हुए उन्होंने बताया कि 15 अगस्त 2027 से देश में बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि अगले साल के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बुलेट ट्रेन की सवारी करने के लिए अभी से टिकट खरीद लीजिए। पहले चरण में सूरत से वापी के बीच 100 किलोमीटर दूरी में ये ट्रेन चलाई जाएगी।

बुलेट ट्रेन में सफर का सपना संजोए हर भारतीय ट्रेन चलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यह ट्रेन न केवल गौरव का प्रतीक है, बल्कि बदलते भारत की तस्वीर भी बयां करेगी। बता दें कि देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलाने की योजना है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद दोनों मेट्रो शहरों के बीच 508 किमी का सफर दो घंटे 17 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का लगभग 55 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। पिछले साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सूरत में प्रोजेक्ट की समीक्षा भी की थी।

320 किमी प्रतिघंटा होगी बुलेट ट्रेन की अधिकतम रफ्तार

2027 में सूरत से वापी के बीच खुलेगा 100 किमी का पहला चरण

508 किमी की दूरी (अहमदाबाद-मुंबई) केवल दो घंटे 17 मिनट में होगी पूरी

55% काम बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का हो चुका है पूरा, 465 किमी का हिस्सा होगा एलिवेटेड

12 स्टेशन होंगे अहमदाबाद-मुंबई के बीच, पहला स्टेशन साबरमती होगा

2017 में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का हुआ था शिलान्यास

2030 के कामनवेल्थ गेम्स से पहले प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद

पूरे रूट में 352 किलोमीटर हिस्सा गुजरात और दादरा व नगर हवेली के बीच और 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में पड़ता है। प्रोजेक्ट को नेशनल हाई-स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) जापान के सहयोग से तैयार करा रहा है। ये ट्रेन जापान की शिंकानसेन हाई-स्पीड ट्रेन की तर्ज पर चलेगी। इसकी अधिकतम रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी पूरे प्रोजेक्ट में कुल 12 स्टेशन पड़ेंगे जिसमें अहमदाबाद, वड़ोदरा, भड़ूच, सूरत, वापी, ठाणे और मुंबई प्रमुख हैं। प्रोजेक्ट का 85 प्रतिशत हिस्सा यानी लगभग 465 किलोमीटर एलिवेटेड होगा जिसमें से 326 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है।

जापान प्रथम, चीन सबसे आगे : चीन, जापान, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, इटली और ताइवान में बुलेट ट्रेनें चलती हैं। इनमें चीन के पास इसका सबसे लंबा नेटवर्क है। जापान ने 1964 में सबसे पहले बुलेट ट्रेन की शुरुआत की थी वहीं फ्रांस और जर्मनी भी हाई-स्पीड रेल के मामले में प्रमुख देश हैं। अमेरिका, इंडोनेशिया और मोरक्को में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है।

गुवाहाटी-कोलकाता के बीच चलेगी पहली स्लीपर वंदे भारत

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन पूरा कर लिया गया है। यह ट्रेन 18-19 जनवरी से गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलाई जा सकती है। ट्रायल रन के दौरान ट्रेन ने 16 कोचों के साथ अधिकतम 182 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी। इसे जल्द ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। वैष्णव ने बताया कि गुवाहाटी-हावड़ा के बीच स्लीपर वंदे भारत के तृतीय एसी का किराया लगभग 2300 रुपये हो सकता है। उन्होंने कहा कि हवाई किराया की बात करें तो ये छह से आठ हजार के बीच होता है और कभी-कभी 10 हजार तक भी पहुंच जाता है। द्वितीय एसी कोच का किराया तीन हजार रुपये और फर्स्ट एसी का किराया 3600 रुपये तक जा सकता है। उन्होंने बताया कि साल के अंत तक देश में 12 स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें चलने के लिए तैयार हो जाएंगी।

Dainik Jagaran Page No-1

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सस्ता और गुणवत्ता में बेहतर होने का मिलेगा लाभ

साल 2030 तक वंदे भारत ट्रेन का निर्यात करेगा रेलवे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जनवरी।

भारतीय रेलवे 2030 तक वंदे भारत ट्रेनों का निर्यात करने की योजना बना रहा है, जिसके लिए वंदे भारत 4.0 नामक एक नया और अधिक उन्नत संस्करण विकसित किया जा रहा है, जिसे विशेष रूप से विदेशी बाजारों के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जिससे भारत दुनिया में आधुनिक रेल तकनीक का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता बन सके। 2029 तक इस ट्रेनों में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा समय में भारतीय रेलवे मोजाम्बिक, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों को डीजल और विद्युत इंजन निर्यात कर रहा है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि वंदे भारत ट्रेन की मांग भारत के कई राज्यों के साथ कई देशों से भी हो रही है। इसके निर्यात करने से पहले दुनियाभर के देशों में उपलब्ध ट्रेनों की गुणवत्ता को इसमें समेटने का प्रयास है। साथ ही इसे दुनियाभर में उपलब्ध ट्रेन से सस्ता रखने की योजना है जिससे निर्यात के समय इसकी मांग बढ़े। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में भारतीय रेलवे 12 देशों के साथ करीब सात हजार करोड़ रुपए का निर्यात कर रहा है। इसे 50 हजार करोड़ रुपए तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।

देश की जरूरत के लिए करीब 200 वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए आदेश दिया गया है। इसकी मदद से देश हर हिस्से को जोड़ने का प्रयास है। मौजूदा समय में बन रही ट्रेन को एक हजार से डेढ़ हजार किमी की यात्रा को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसमें सुधार कर इसे तीन हजार किमी तक भी ले जाने की योजना है। मंत्री का कहना है कि ट्रेनों को विश्व स्तर का बनाने के लिए साल 2027 से एल्यूमिनियम धातु से ट्रेनें बनाने की दिशा में प्रयास शुरू होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में काम कर रहा है।

कृत्रिम मेधा आधारित कैमरे देंगे पटरी के पास वन्यजीव की जानकारी

मंत्री ने कहा कि अगले छह माह में सभी लोकोमोटिव को कृत्रिम मेधा आधारित कैमरे से सुसज्जित किया जाएगा। यह कैमरे ट्रेन चालक को 500 मीटर पहले ही पटरियों पर वन्यजीवों की जानकारी दे देंगे। मौजूदा समय में रेलवे पटरियों के आसपास वन्य जीवों की चहल पहल को पकड़ने के लिए आप्टिकल फाइबर तार लगाए गए हैं। इसकी मदद से 200 मीटर के दायरे में वन्यजीवों की चहल-पहल का पता चल जाता है। मंत्री ने कहा कि देश में करीब तीन हजार किलोमीटर क्षेत्र में वन्यजीवों का प्रभाव रहता है। इन दोनों तकनीक की सुविधा उपलब्ध हो जाने के बाद दुर्घटनाएं होने की आशंका कम हो जाएगी।

हावड़ा से गुवाहाटी तक चलेगी देश की पहली वंदे भारत शयनयान ट्रेन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जनवरी।

देश की पहली वंदे भारत शयनयान ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 या 18 जनवरी को कोलकाता से इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं। हावड़ा से गुवाहाटी के बीच इस ट्रेन का किराया तीसरी श्रेणी में 2300, दूसरी श्रेणी में तीन हजार और पहली श्रेणी में 3600 रुपए प्रति यात्री तय हो सकता है। यह ट्रेन रात के समय अपने स्थान से रवाना होगी और अगले दिन सुबह गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी।

> 17 या 18 जनवरी को प्रधानमंत्री कोलकाता से दिखा सकते हैं हरी झंडी।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले दिनों इस ट्रेन का परीक्षण 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से किया गया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व उदय कार्यक्रम के तहत इस मार्ग का चयन किया गया है। ट्रेन में कुल 16 डिब्बे होंगे। इसमें 11 डिब्बे तीसरी वातानुकूलित श्रेणी के, चार दूसरी श्रेणी के और एक डिब्बा पहली वातानुकूलित श्रेणी का होगा। ट्रेन में कुल 823 यात्री सफर कर सकेंगे। आम लोगों की पहुंच को देखते हुए इसका किराया 2.4 रुपए प्रति किमी से 3.6 रुपए प्रति किमी लेने का फैसला लिया गया है।

मंत्री ने कहा कि अगले छह माह में 12 और वंदे भारत ट्रेनें मिलने की संभावना है, जिन्हें छह और मार्ग पर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि एक से डेढ़ हजार किमी की दूरी के लिए इस तरह की ट्रेन को चलाया जाए।

Jansatta Page No-10

कृत्रिम बुद्धिमता पर अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की तैयारी

दिल्ली की मुख्य जगहों का होगा कायाकल्प

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जनवरी।

> 15 से 20 फरवरी के बीच होगा अंतरराष्ट्रीय एआइ प्रभाव शिखर सम्मेलन।

> *मुख्य* सचिव ने जी-20 से बेहतर तैयारी के निर्देश दिए, कई सड़कों और पर्यटनों स्थलों के आसपास के नवीनीकरण की कार्ययोजना तैयार, अन्य विभागों के साथ तालमेल बनाने को पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित

राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी माह में कृत्रिम बुद्धिमता पर अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। एआइ प्रभाव शिखर सम्मेलन (एआइ इम्पैक्ट समिट) में दुनियाभर से विदेशी मेहमान शिरकत करेंगे। 15 से 20 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन से पहले लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने भारत मंडपम, आइजीआइ हवाई अड्डे और शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के आसपास के क्षेत्रों के व्यापक कायाकल्प करने की योजना बनाई है।

दिल्ली सरकार ने पीडब्ल्यूडी और अन्य नगर निकायों को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन के लिए व्यवस्थाएं जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान निर्धारित मानकों से ज्यादा बेहतर तरीके से की जाएं।

इस आयोजन को लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव की ओर से सुरक्षा, यातायात, गणमान्य व्यक्तियों की आवाजाही, स्वच्छता, सड़क की स्थिति, संकेतक, प्रकाश व्यवस्था और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के साथ साथ बाजारों का कायाकल्प करने के निर्देश दिए गए हैं। इस सबको लेकर नवीनीकरण कार्ययोजना तैयार की गई है। शिखर सम्मेलन 15-20 फरवरी तक आयोजित होगा जिसमें 19 फरवरी को मुख्य उद्घाटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन के लिए भारत मंडपम को स्थल के रूप में चुना गया है। इस दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी यहां पर आयोजित की जाएंगी।

कार्य योजना में पीडब्ल्यूडी की सड़कों और फुटपाथों के रखरखाव को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें गड्ढों को भरना, गायब संकेतक बोर्डों को दुरूस्त करना, क्षतिग्रस्त ग्रिलों को हटाना, मध्य किनारों (सेंट्रल वर्ज) की मरम्मत और सुधार करने के अलावा सुरक्षा व बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार लाने को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। इसके साथ ही अंधेरे क्षेत्रों (डार्क स्पाट) की समस्या को भी दूर किया जाएगा।

पीडब्ल्यूडी को भारत मंडपम के आसपास के क्षेत्र को जिम्मा सौंपा गया है, जहां हैदराबाद हाउस, विज्ञान भवन, अंबेडकर भवन, सुषमा स्वराज भवन, सभी पांच बड़े पांच सितारा होटल और राजघाट के आसपास आदि का कायाकल्प किया जाएगा। इन जगहों पर मुख्य कार्यक्रम से पहले की गतिविधियां और द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा, कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, कनाट प्लेस, सेंट्रल पार्क, दिल्ली हाट और महरौली पुरातत्व पार्क जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाली सड़कों के नवीनीकरण करने की योजना भी कार्ययोजना में शामिल की गई।

Jansatta Page No-2

मंथन

मुख्तार अब्बास नकवी
पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव

मोदी पर इस्लामी दुनिया का भरोसा

छद्म सेक्युलर सिंडिकेट के राजनीतिक असहिष्णुता, अस्पृश्यता और वर्षों दुराग्रहपूर्व दुष्प्रचार को दरकिनार करके भारत की जनता द्वारा वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी को दिए गए जनादेश के बाद देश में बनी मोदी सरकार सुशासन के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है

वर्ष 2014 से शुरू हुआ मोदी सुशासन का सफल सफर कोई 'केकवाक' या फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों का ताज रहा। विरासत में मिली बिगड़ी हुई व्यवस्था, बेहाल अर्थतंत्र, प्रधानमंत्री संस्थान की धराशाई धाक-धमक का देश गवाह था। दिल्ली के सत्ता के गलियारे में सत्ता के दलालों और लूट लाबी की समानांतर व्यवस्था का बोलबाला किसी से छिपा नहीं था। सांप्रदायिक तुष्टीकरण की सियासत ने समावेशी सशक्तीकरण के सोच को बंधक बना रखा था। मोदी सरकार बनते ही सत्ता के दलालों की नाकेबंदी, डपोरशंखों द्वारा असहिष्णुता का हंगामा, पुरस्कार वापसी का हुड़दंग, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर खतरे का हाहाकार, तमाम इस्लामी देशों से रिश्तों की कुट्टी का काल्पनिक भ्रम जैसे सैकड़ों सवालों को उछालकर मोदी सरकार के प्रति दुष्प्रचार करता रहा। लेकिन इन 11 वर्षों में मोदी ने भारत के प्रभाव को वैश्विक स्तर पर बढ़ाया।

वर्ष 2014 में जिस बात का सबसे ज्यादा शोर किया गया था, वह थी इस्लामी दुनिया या देशों से भारत की कुट्टी और रिश्तों की छुट्टी का हवा-हवाई दावा। देश व देश के बाहर चलाए जा रहे मोदी और मुल्क के खिलाफ इन सुनियोजित साजिशों के संक्रमणों का सूपड़ा साफ करते मोदी के शासनकाल में तमाम इस्लामी देशों के साथ भारत के बेहतरीन और बेमिसाल रिश्ते ही नहीं बने, बल्कि उन देशों के साथ राजनयिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, आर्थिक ताना-बाना भी शानदार रहा। इन शक्तिशाली इस्लामिक देशों ने भारत और मोदी के प्रति विश्वास को प्रदर्शित करते हुए अपने सर्वोच्च सम्मानों से भारत और नरेन्द्र मोदी को नवाजा। यही नहीं, दुनियाभर के तमाम अन्य देशों में भी मोदी के प्रभावशाली नेतृत्व के प्रति विभिन्न सम्मानों से सम्मानित करने की लंबी श्रृंखला रही। तमाम देशों के साथ राजनयिक-व्यावसायिक रिश्तों व आतंक की चुनौतियों से साझा तौर पर निपटने की प्रतिबद्धता भी शामिल रही।

जो नेता भारत में दशकों सर्वाधिक राजनीतिक असहिष्णुता और अस्पृश्यता एवं दुराग्रह पूर्व दुष्प्रचार का शिकार रहा हो, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिनके खिलाफ षड्यंत्रों की पराकाष्ठा रही हो, उनकी तपस्या की ताकत, परिश्रम का परिणाम है कि भारत तमाम संकटों-कंटकों, वैश्विक आर्थिक तंगी-मंदी से उबर कर विश्व की सबसे मजबूत उभरती हुई शक्तिशाली अर्थव्यवस्था स्थापित करने में कामयाब रहा। इन तमाम दुष्प्रचारों और दुराग्रहों को दरकिनार करके आज तमाम इस्लामिक देशों के नेतृत्व के मोदी न केवल चहेते हैं, बल्कि उनसे व्यक्तिगत दोस्ताना संबंधों के चलते भारत आर्थिक, व्यापारिक, रोजगार के क्षेत्र में बेहतरीन युग का साक्षी बना है। यह सबकुछ बिना तुष्टीकरण समावेशी सशक्तीकरण के बलबूते नरेन्द्र मोदी करने में कामयाब हुए हैं। यही नहीं, इस्लाम को सुरक्षा कवच बनाकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और उसके पालतू जालिमों को भी जमींदोज किया और मुल्क एवं मानवता को मजबूत करने के लिए बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ते रहे।

विश्व का भरोसा जीता : वैचारिक एवं सैद्धांतिक प्रतिबद्धता से किसी तरह का समझौता किए बिना नरेन्द्र मोदी ने दुनियाभर का विश्वास हासिल किया, चाहे अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राममंदिर का निर्माण हो या जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति हो या तीन तलाक की कुरीति, कुप्रथा पर नियंत्रण का कानून या फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के पीड़ित, प्रताड़ित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा-सम्मान संरक्षण हेतु सीएए में संशोधन या घुसपैठियों के सफाए हेतु एनआरसी अभियान, सामाजिक आर्थिक, शैक्षणिक प्रशासनिक और चुनाव सुधार के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहे।

पिछले 11 वर्षों के राष्ट्रीय सियासी मंथन ने "कुनबे की अकड़, कुशासन की जकड़" को पछाड़ कर 'परिश्रम के परिणाम ने बाजी मारी है", पुश्तैनी सियासत, खानदानी विरासत के जहर को अलग थलग कर संकट के दौर, कंटक के काल में सुशासन की शक्ति परिश्रम के परिणाम से दुनिया में भारत की धाक और मोदी की धमक ने 'अमृत काल' में प्रमाणित कर दिया है कि "भाजपा शासन की स्वाभाविक पार्टी और नरेन्द्र मोदी सुशासन के सशक्त पर्याय" बन गए हैं।

नरेन्द्र मोदी। फाइल

मोदी ने कभी भी विकास के मसौदे को वोट के सौदे से नहीं जोड़ा, किसी भी संप्रदाय या वर्ग की उनके साथ की गई वोटों की कंजूसी के बावजूद उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक सशक्तीकरण में कमी नहीं होने दी। यही कारण है कि वह वर्ग भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रिवाज को समावेशी सशक्तीकरण का मिजाज बना रहे हैं। इस्लामिक देशों के साथ बढ़ते रिश्तों का सबसे ज्वलंत उदाहरण ओमान का है, जहां भारतीयों के लिए काम करने, व्यापार करने का रास्ता ऐतिहासिक रूप से सुलभ और सरल हुआ है।

Dainik Jagaran Page No-9

एकाग्रता का संकट बढ़ा, 'फोकस एप्स' बन रहे समाधान

अध्ययन ▶ 'फोकस फ्रेंड' जैसे एप में टाइमर सेट करके एकाग्रता बढ़ाने पर कर सकते हैं काम

क्राइस्टचर्च (न्यूजीलैंड), द कन्वरसेशन: अगर स्मार्टफोन हमारी एकाग्रता भंग कर रही है तो इसका निदान भी वहीं मौजूद है। इसके लिए कुछ इनोवेटर ऐसे एप लेकर आए हैं, जो एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। ये 'फोकस और प्रोडक्टिविटी एप्स' टाइमर, एप-ब्लाकिंग, गेमिफिकेशन और इनाम के जरिए ध्यान केंद्रित रखने का दावा करते हैं। यूनिवर्सिटी आफ कैंटरबरी के इवेन एलन ने इन एप का अध्ययन किया कि ये कितने कारगर हैं। निष्कर्ष में उन्होंने पाया कि सीमित समय के लिए इन एप्स का इस्तेमाल अपनी आदत विकसित करने में किया जा सकता है।

क्यों भटकता है ध्यान: विशेषज्ञ बताते हैं कि ध्यान भटकने की जड़ तकनीक नहीं, बल्कि हमारी भावनाएं और आदतें हैं। जब कोई काम उबाऊ, कठिन या तनावपूर्ण लगता है, तो मन उससे बचने का रास्ता खोजता है। स्मार्टफोन इस बचाव का सबसे आसान

प्रतीकात्मक

जरिया बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि शोध यह नहीं कहते कि इंसान की फोकस करने की क्षमता कम हो गई है, बल्कि यह जरूर बताते हैं कि आज का माहौल हमारे ध्यान पर पहले से कहीं ज्यादा दबाव डालता है। लगातार डिजिटल व्यवधान और मल्टीटास्किंग से कुछ लोगों में ध्यान भटकने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

एकाग्रता बढ़ाने वाले एप: इसी पृष्ठभूमि में 'फोकस फ्रेंड' जैसे एप सामने आए हैं। यह एप एक वर्चुअल कैरेक्टर के जरिए यूजर को तय समय तक फोन से दूर रहकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। फोकस सत्र पूरा होने पर डिजिटल इनाम मिलते हैं, जबकि नियम तोड़ने पर नुकसान होता है। इसमें प्रोत्साहन, प्रतिबद्धता व 'आइकिआ इफेक्ट' जैसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल किया गया है। आइकिया इफेक्ट में खुद की बनाई या जोड़ी गई वस्तुओं को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। फोकस फ्रेंड एप पिछले साल अगस्त में लांच हुआ और पहले ही महीने में डाउनलोड किए जाने में चैटजीपीटी को पीछे छोड़ दिया।

आदत बनाने में कारगर हो सकते हैं फोकस एप: हालांकि, फोकस एप्स की प्रभावशीलता पर शोध अभी सीमित हैं। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि गेमिफाइड एप्स यूजर्स को पसंद तो आते हैं, लेकिन लंबे समय तक उनका उपयोग कम होता है और वे सरल उपायों- जैसे फोन को ग्रेस्केल मोड में डालना- से भी कम प्रभावी साबित होते हैं। केवल मनोरंजन या आनंद मिलना उत्पादकता बढ़ने की गारंटी नहीं है। एलन ने बताया कि यदि किसी को काम के दौरान बार-बार फोन देखने की आदत है, तो सीमित समय के लिए फोकस एप आजमाए जा सकते हैं। साथ ही यह भी जरूरी है कि यूजर अपने अनुभव की समीक्षा करें और समझें कि एप उनकी मदद कर रहा है या वे एप के गुलाम बनते जा रहे हैं। अंत में, फोकस एप्स एक सहारा हो सकते हैं, लेकिन असली लड़ाई भीतर की है। ध्यान भटकने के कारणों को समझना, असहजता को स्वीकार करना और जरूरी काम पर टिके रहने का फैसला ही लंबे समय में फोकस वापस ला सकता है।

Dainik Jagaran Page No-14

EDU TERIA

EDU TERIA

Website : eduteriatestseries.com

झारखंड डायरी

बाबा कार्तिक उरांव के बहाने आदिवासी राजनीति

शशि शेखर
संपादकीय प्रभारी, रांची

झारखंड के गुमला जिले के रायडीह प्रखंड के माझाटोली स्थित बैरियर बगीचा परिसर में हाल ही में अंतरराज्यीय जन सांस्कृतिक समागम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मुख्य अतिथि थीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वहां के राज्यपाल भी इस समारोह में शामिल हुए। यह क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सीमा पर है। आयोजन भाजपा के पूर्व विधायक शिवशंकर उरांव ने किया था। यहां हर साल बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर जतरा यानी मेले का आयोजन होता है, जहां तीनों प्रदेशों के आदिवासी एकत्रित होते हैं। इस बार भी तीनों राज्यों के लोग वहां पहुंचे।

झारखंड में सत्ता से बाहर भाजपा सत्ता में वापसी के लिए आदिवासी मतों को अपनी ओर करना चाहती है। इसलिए वह आदिवासी मुद्दों को प्रखरता से उठा रही है, लेकिन झामुमो गठबंधन सरकार अपने पारंपरिक मतों में बिखराव नहीं चाहती। हाल ही में झारखंड सरकार ने पेसा (पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र) नियमावली को कैबिनेट से पास कर आदिवासियों से जुड़ा एक और बड़ा मुद्दा अपने पाले में कर लिया है। लंबे समय से झारखंड में इसे लागू करने की मांग की जा रही थी। हालांकि भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड में स्वीकृत की गई पेसा नियमावली को केंद्र के पेसा कानून की मूल भावना के विपरीत बताया है। उन्होंने नियमावली में किए गए संशोधनों पर सवाल उठाए हैं। दास ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कैबिनेट द्वारा स्वीकृत नियमावली में अब तक जो भी बातें सामने आई हैं, उनके अनुसार राज्य सरकार ने ग्रामसभा की परिभाषा में परंपरागत जनजातीय नेतृत्व और सामाजिक संरचना को सीमित कर

गुमला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को स्मृतिचिह्न भेंट करते भाजपा नेता शिवशंकर उरांव। फाइल

दिया है, जबकि पेसा अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा का गठन और संचालन स्थानीय परंपराओं, सामाजिक-धार्मिक व्यवस्थाओं के अनुरूप होना चाहिए।

झारखंड में मतांतरण एक बड़ा मुद्दा रहा है। आदिवासियों की गरीबी और कमजोर हालत का फायदा उगाकर ईसाई मिशनरियों ने प्रलोभन का जाल फैलाकर यहां बड़े पैमाने पर उन्हें ईसाई बना दिया है। ऐसे मतांतरित आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर निकालने की मांग भी उठती रही है। वह दोहरा लाभ न ले सकें, इसलिए डीलिस्टिंग की मांग की जाती है। एक समय में कांग्रेस के प्रतिष्ठित व कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय कार्तिक उरांव ने भी यह बात जोर-शोर से उठाई थी। भाजपा एक बार फिर इन मुद्दों को धार दे रही है। बाबा कार्तिक उरांव ने ही सबसे पहले संसद में डीलिस्टिंग का मुद्दा उठाया था और उन्होंने 20 वर्ष की काली रात पुस्तिका लिखकर बताया कि किस प्रकार मतांतरित आदिवासी सरना आदिवासियों के अधिकार को लूट रहे हैं। हालांकि अब राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस की कौन कहे, स्वयं कार्तिक उरांव की बेटी व पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव भी इस मुद्दे को नहीं उठातीं। इसे अब भाजपा और उससे जुड़े आदिवासी संगठन जोर-शोर से उठा रहे हैं। कांग्रेस बाबा कार्तिक उरांव के विचारों से बहुत दूर खड़ी है। वह उनकी जयंती को भी याद नहीं करती। हां, हाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में एक फ्लाईओवर का नाम उनके नाम पर कर एक संदेश देने की कोशिश की है।

बाबा कार्तिक उरांव सरना आदिवासी थे। गुमला जिले के करौंदा गांव की लीलाटोली में 29 अक्टूबर, 1924 को उनका जन्म हुआ था और आठ दिसंबर, 1981 को निधन। देश-विदेश में पढ़े। लंदन में नौकरी की। जब नेहरू लंदन गए थे, वहां इनकी प्रतिभा देख इन्हें वापस देश ले आए। रांची में तब एचइसी की स्थापना होनी थी और कार्तिक उरांव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। कांग्रेस को भी एक कद्दावर आदिवासी नेता की जरूरत थी। पं. नेहरू को कार्तिक उरांव में वह प्रतिभा दिखी और फिर उन्हें चुनाव में उतारा। लोकसभा व विधानसभा में भागीदारी की। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में भी रहे। 1967 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की और उसके पहले संस्थापक अध्यक्ष बने।

आज कार्तिक उरांव का विचार भाजपा को भा रहा है और वह इनके बहाने आदिवासियों के बीच अपने प्रति विश्वास पैदा करना चाहती है। पर, गांव-गांव ईसाई मिशनरियों की पैठ और उनके काम करने के तरीके को भांपना बहुत मुश्किल है। बाबा कार्तिक का जोर शिक्षा पर था, ताकि शिक्षित हो जाएंगे तो मतांतरण नहीं होगा। इसीलिए वे तीनों राज्यों की सीमा पर एक विवि की स्थापना करना चाहते थे जिससे तीनों राज्यों के आदिवासी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। 1981 से यह ठंडे बस्ते में है। अब फिर इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। देखना यह है कि भाजपा बाबा कार्तिक उरांव के बहाने इस मुद्दे को कहां और कितना दूर लेकर जाती है?

Dainik Jagaran Page No-9

वैज्ञानिक विमर्श के केंद्र में ब्रह्मांड का भविष्य

प्रदीप

ऐसे संकेत मिले हैं कि ब्रह्मांड के विस्तार की गति अब पहले जितनी तेज नहीं रही

दक्षिण कोरिया की योंसेई यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ब्रह्मांड के भविष्य को लेकर दशकों से चली आ रही मान्यताओं पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वस्तुतः अब तक हमारी यह धारणा थी कि ब्रह्मांड का त्वरित गति से लगातार विस्तार हो रहा है। यह मान्यता 1998 में सामने आए उन शोधों पर आधारित थी, जिनमें दूरस्थ सुपरनोवा के प्रेक्षण से कृष्ण ऊर्जा (डार्क एनर्जी) नामक एक रहस्यमय शक्ति का पता चला था। माना गया कि यही शक्ति मंदाकिनियों को एक-दूसरे से दूर धकेल रही है, जिससे भविष्य में ब्रह्मांड का अंत एक ठंडे और खामोश परिदृश्य में होगा।

लेकिन 'मंथली नोटिसेज आफ द रायल एस्ट्रोनामिकल सोसायटी' में प्रकाशित अपने एक अध्ययन में योंसेई यूनिवर्सिटी के नए अध्ययन ने इस तस्वीर को जटिल बना दिया है। उनके विश्लेषण में यह संकेत मिला है कि ब्रह्मांड के विस्तार की गति अब पहले जितनी तेज नहीं रही। उनका दावा है कि जब सुपरनोवा की चमक को अधिक गहराई से जांचा गया, तो यह स्पष्ट हुआ कि उनका प्रकाश केवल दूरी पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि उन तारों की आयु पर भी निर्भर करता है जिनसे सुपरनोवा विस्फोट पैदा होते हैं। नए शोध से यह भी पता चला है कि पुराने तारों से उत्पन्न सुपरनोवा अपेक्षाकृत अधिक चमकीले होते हैं, जबकि युवा तारों से आने वाले विस्फोट थोड़े धुंधले प्रतीत होते हैं। इसका मतलब यह है कि पहले जिस धुंधलेपन को ब्रह्मांडीय विस्तार का संकेत माना गया था, वह आंशिक रूप से तारों की भौतिक प्रकृति का नतीजा भी हो सकता है।

जब शोधकर्ताओं ने इस 'आयु प्रभाव' को गणनाओं में शामिल किया, तो कृष्ण ऊर्जा को स्थिर मानने वाला वर्तमान माडल कमजोर पड़ गया। संशोधित आंकड़ों से यह संकेत मिला कि कृष्ण ऊर्जा समय के साथ कमजोर हो सकती है। यदि यह बात सही साबित होती है, तो भविष्य में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बढ़ सकता है और मंदाकिनियां विस्तृत होने की जगह एक-दूसरे की ओर खिंचने लगेंगी। यहीं से 'बिग क्रंच' (महा-संकुचन) की परिकल्पना दोबारा से चर्चा में आ गई है, जिसके मुताबिक ब्रह्मांड का विस्तार एक समय रुक जाएगा और फिर वह सिमटने लगेगा, अंततः एक अत्यंत सघन अवस्था में पहुंच जाएगा। यह विचार नया नहीं है, लेकिन हालिया आंकड़ों ने इसे फिर से वैज्ञानिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

हालांकि इस निष्कर्ष से सभी सहमत नहीं हैं। कई विज्ञानियों का मानना है कि सुपरनोवा के आंकड़े अत्यंत जटिल होते हैं और उनमें किए गए छोटे सुधार भी बड़े परिणामों को उत्पन्न कर सकते हैं। उनका कहना है कि अभी यह तय करना उतावलापन होगा कि कृष्ण ऊर्जा वास्तव में कमजोर हो रही है। बहरहाल, आने वाले वर्षों में और सटीक प्रेक्षणों से यह स्पष्ट हो सकेगा कि ब्रह्मांड वास्तव में धीमे विस्तार की ओर बढ़ रहा है या नहीं।

(लेखक विज्ञान संचारक हैं)

Dainik Jagaran Page No-8

कैलाश बिश्नोई

उच्च शिक्षा मामलों के जानकार

आजकल

भारतीय उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण

वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था के वर्तमान दौर में उच्च शिक्षा राष्ट्रों की आर्थिक सामर्थ्य, कूटनीतिक प्रभाव और मानव संसाधन प्रतिस्पर्धा का निर्णायक आधार बन चुकी है। इसी संदर्भ में नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट 'भारत में उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण : संभावनाएं, क्षमता एवं नीतिगत सिफारिशें' देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था का यथार्थ आकलन प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट इस संदर्भ में प्रश्न उठाती है कि बड़े पैमाने पर संस्थानों और अपेक्षाकृत किफायती शिक्षा के बावजूद भारत विदेशी छात्रों को आकर्षित करने में क्यों पिछड़ रहा है

प्रतीकात्मक

नीति आयोग की उच्च शिक्षा पर आधारित रिपोर्ट केवल आंकड़ों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि भारत की बौद्धिक यात्रा का आत्मालोचन है। जिस देश के पास 18-23 वर्ष आयु वर्ग की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, वही देश आज अंतरराष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा निर्यातक भी बन चुका है। वर्ष 2024 में 13.35 लाख से अधिक भारतीय छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं। यह संख्या अपने आप में गर्व का विषय नहीं, बल्कि एक सवाल है। सवाल यह नहीं कि भारतीय छात्र विदेश क्यों जाते हैं, बल्कि यह है कि वे भारत में क्यों नहीं रुकते।

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां अंतरराष्ट्रीयकरण ब्रेन ड्रेन को ब्रेन सर्कुलेशन में बदल सकता है। यदि वैश्विक विवि भारत आएं, संयुक्त डिग्री और शोध कार्यक्रम विकसित हों व घरेलू संस्थानों को वैश्विक नेटवर्क से जोड़ा जाए तो आने वाले वर्षों में वही भारत, जो आज छात्रों को भेज रहा है, ज्ञान और प्रतिभा को आकर्षित करने वाला केंद्र भी बन सकता है।

शिक्षा हमेशा से भारत की साफ्ट पावर रही है। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में पूरे विश्व से विद्यार्थी आते थे। ज्ञान की यह धारा एकतरफा नहीं थी, बल्कि संवादात्मक थी। आज स्थिति उलट है। हर एक विदेशी छात्र के मुकाबले 28 भारतीय छात्र विदेश जा रहे हैं। यह अनुपात केवल ब्रेन ड्रेन नहीं, बल्कि नीतिगत विफलता का संकेत देता है। नीति आयोग ठीक ही कहता है कि उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता है।

वर्तमान स्थिति की बात करें तो कनाडा भारतीय छात्रों का सबसे पसंदीदा गंतव्य बन चुका है। 2024 में वहां 4.27 लाख भारतीय छात्र पढ़ रहे थे। अमेरिका में 3.37 लाख, ब्रिटेन में 1.85 लाख और आस्ट्रेलिया में 1.22 लाख छात्र हैं। जर्मनी में लगभग 43 हजार भारतीय छात्र हैं। इन आंकड़ों के पीछे केवल बेहतर विवि रैंकिंग नहीं है, बल्कि वीजा नीति, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट और रोजगार की संभावनाएं भी हैं। कनाडा का उदाहरण लें जहां पढ़ाई के साथ काम करने और स्थायी निवास की राह अपेक्षाकृत आसान रही है। यही कारण है कि पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में युवा वहां पहुंच रहे हैं। यह एक तरह से आधुनिक समय का प्रवासन है जहां खेत से कारखाने की जगह गांव से वैश्विक विश्वविद्यालय तक की यात्रा हो रही है।

लेकिन इस यात्रा की कीमत भी भारी है। वर्ष 2023-24 में केवल चार देशों कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले 8.5 लाख भारतीय छात्रों ने लगभग 2.9 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। यह राशि कई भारतीय राज्यों के वार्षिक बजट से अधिक है। यह धन यदि देश में ही अनुसंधान प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप, इनक्यूबेटर और विश्वविद्यालयों पर खर्च होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती। नीति आयोग की रिपोर्ट इस असंतुलन को स्वीकार करती है और समाधान भी सुझाती है। उदाहरण के लिए 10 अरब डालर के भारत विद्या कोष का प्रस्ताव एक साहसिक कदम है। इसमें 50 प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्र और डायस्पोरा से आने की बात कही गई है। यह फंड अनुसंधान को गति दे सकता है, क्योंकि भारत का अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय (जीईआरडी) आज भी जीडीपी का केवल 0.7 प्रतिशत है, जबकि विकसित देशों में यह दो से तीन प्रतिशत तक है। यदि भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनना है तो प्रयोगशालाओं में निवेश उतना ही जरूरी है जितना सड़कों और पुलों में।

शिक्षा संसाधनों का विकास : राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की भूमिका यहां निर्णायक है, क्योंकि भारत के 81 प्रतिशत छात्र इन्हीं में पढ़ते हैं। लेकिन यही संस्थान सबसे अधिक उपेक्षित भी हैं। तमाम रिपोर्ट यह इंगित करते हैं कि 40 प्रतिशत फैकल्टी पद खाली हैं और केवल 10 प्रतिशत उच्च शिक्षण संस्थानों में ही पर्याप्त शोध सुविधाएं हैं। यह स्थिति उस किसान की तरह है जिसके पास जमीन तो है, लेकिन बीज और पानी नहीं। अंतरराष्ट्रीयकरण का अर्थ केवल छात्रों को विदेश भेजना नहीं, बल्कि विदेश को भारत लाना भी है। विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस भारत में खोलने का प्रस्ताव इसी सोच का हिस्सा है। गुजरात का गिफ्ट सिटी माडल एक उदाहरण है, जहां विदेशी संस्थानों को नियामकीय छूट दी गई। यदि यह माडल सफल होता है तो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहर वैश्विक शिक्षा मानचित्र पर उभर सकते हैं। इससे न केवल भारतीय छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा देश में मिलेगी, बल्कि विदेशी छात्र भी आकर्षित होंगे। नीति आयोग का लक्ष्य 2047 तक पांच लाख से अधिक विदेशी छात्रों को भारत लाने का है। यह लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन असंभव नहीं।

कम नहीं चुनौतियां : इस लक्ष्य प्राप्ति की राह में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। गुणवत्ता व समानता के बीच संतुलन एक बड़ी चुनौती है। तमिलनाडु जैसे राज्यों में जीईआर 47 प्रतिशत तक है, जबकि बिहार में शिक्षा पर खर्च जीएसडीपी का केवल 1.56 प्रतिशत है। यह क्षेत्रीय असमानता अंतरराष्ट्रीयकरण के प्रयासों को कमजोर कर सकती है। यदि कुछ चुनिंदा राज्य ही वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेंगे तो देश के भीतर ही एक नया शैक्षिक विभाजन खड़ा हो जाएगा।

ब्रेन ड्रेन की समस्या का एक मानवीय पहलू भी है। विदेश जाने वाला छात्र केवल बेहतर शिक्षा नहीं, बल्कि सम्मान और अवसर की तलाश में जाता है। जब एक युवा इंजीनियर भारत में वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है और अंततः जर्मनी या आयरलैंड में जाकर शोध के अवसर पाता है तो यह हमारे सिस्टम पर प्रश्न खड़ा करता है। नीति आयोग का दृष्टिकोण इसीलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह शिक्षा को केवल सामाजिक सेवा नहीं, बल्कि रणनीतिक निवेश मानता है। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि शिक्षा सुधारों का असर चुनावी चक्र से परे होता है, इसलिए इसे दीर्घकालिक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में देखना होगा। जिस दिन भारत का छात्र विदेश जाकर यह कहे कि वह विकल्प नहीं मजबूरी में गया था और विदेशी छात्र भारत आकर यह महसूस करे कि उसने अवसर चुना है, उसी दिन समझिए कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। यही वह मोड़ है जहां से ब्रेन ड्रेन ब्रेन गेन में बदलेगा और भारत फिर से ज्ञान का विश्वसनीय केंद्र बनेगा।

प्रगति पथ पर अग्रसर भारत की अकादमिक उड़ान

नीति आयोग की रिपोर्ट ने जो आईना दिखाया है उसके बाद अब आधे-अधूरे सुधारों से काम नहीं चलेगा। भारत को यह तय करना होगा कि वह केवल छात्रों का आपूर्तिकर्ता बना रहेगा या ज्ञान का निर्माता भी बनेगा। इस निर्णय से ही आगे की दिशा तय होगी। सबसे पहली आवश्यकता मानसिकता के बदलाव की है। उच्च शिक्षा को अब खर्च नहीं, बल्कि दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखना होगा। जिस तरह बुनियादी ढांचे पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं, उसी तरह विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों पर खर्च को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक संप्रभुता से जोड़कर देखना होगा। यदि भारत रक्षा आयात कम करना चाहता है, डिजिटल आर्थिकी में नेतृत्व व जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटना चाहता है तो उसे अपनी प्रयोगशालाओं और कक्षाओं को मजबूत करना ही होगा।

दूसरी राह राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के पुनरुत्थान से होकर जाती है। ये विश्वविद्यालय भारत की रीढ़ हैं, लेकिन सबसे कमजोर कड़ी भी। यहां फैकल्टी की भर्ती को मिशन मोड में लाना होगा। केवल संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता पर जोर देना होगा। उद्योग और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से संयुक्त नियुक्ति और विजिटिंग प्रोफेसर माडल अपनाए जा सकते हैं। इससे ज्ञान का प्रवाह होगा और छात्रों को वैश्विक दृष्टि मिलेगी। साथ ही इन विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम तय करने और फीस संरचना में सीमित, लेकिन वास्तविक स्वायत्तता देनी होगी, ताकि वे स्थानीय जरूरतों और वैश्विक मानकों के बीच संतुलन बना सकें।

तीसरी दिशा अनुसंधान और नवाचार को केंद्र में रखने की है। 10 अरब डालर भारत विद्या कोष तभी सार्थक होगा, जब उसका उपयोग पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी ढंग से हो। केवल चुनिंदा संस्थानों को ही नहीं, बल्कि उभरते विश्वविद्यालयों और राज्य स्तर की शोध इकाइयों को भी अवसर देना होगा। डायस्पोरा वैज्ञानिकों को भारत लौटने या आंशिक रूप से जुड़ने के लिए आकर्षक माडल बनाने होंगे। अल्पकालिक प्रोजेक्ट और संयुक्त लैब्स इस दिशा में प्रभावी हो सकते हैं। चौथी राह अंतरराष्ट्रीयकरण को भारत के भीतर लाने की है। विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस केवल महानगरों तक सीमित न रहें बल्कि टियर-2 शहरों में भी विकसित हों। इससे क्षेत्रीय असमानता कम होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। संयुक्त डिग्री और ट्विनिंग प्रोग्राम्स के जरिए भारतीय छात्र आधी पढ़ाई देश में और आधी विदेश में कर सकेंगे। इससे लागत भी घटेगी और गुणवत्ता भी बढ़ेगी।

पांचवीं दिशा डिजिटल और एआइ आधारित शिक्षा के विवेकपूर्ण उपयोग की है। आनलाइन प्लेटफार्म केवल वीडियो लेक्चर तक सीमित न रहें, बल्कि मेंटरशिप, वर्चुअल लैब्स और वैश्विक क्लासरूम का माध्यम बनें। इससे बिहार, छत्तीसगढ़ या पूर्वोत्तर का छात्र भी वही अवसर पा सकेगा जो आज केवल चुनिंदा शहरों तक सीमित हैं। लेकिन इसके साथ शिक्षक प्रशिक्षण और स्थानीय भाषाओं में कंटेंट पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा। छठी राह वीजा और छात्र अनुकूल नीतियों से होकर जाती है। यदि भारत विदेशी छात्रों को आकर्षित करना चाहता है तो प्रवेश से लेकर डिग्री के बाद रोजगार तक एक स्पष्ट और सरल मार्ग देना होगा। वर्क परमिट, इंटर्नशिप और स्टार्टअप वीजा जैसे विकल्प भारत को प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं। यह केवल शिक्षा नहीं बल्कि सांस्कृतिक कूटनीति का भी माध्यम होगा। **(कैलाश बिश्नोई)**

Dainik Jagaran Page No-9

शिक्षा से सशक्त हो रहा है समाज

विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है, जब समाज का प्रत्येक वर्ग शिक्षा और अवसरों से समान रूप से जुड़ सके। वर्ष 2026 की ओर बढ़ते हुए दैनिक जागरण के विशेष समाचारीय अभियान 'उम्मीदें-2026' में उन प्रयासों को सामने लाया जा रहा है, जो जमीनी स्तर पर समाज की दिशा और दशा बदल रहे हैं।

स्वस्थ समाज के बाद अगली कड़ी में सुशिक्षित समाज की उस तस्वीर को उकेरा गया है, जहां श्रमिकों और रिक्शा चालकों के बच्चे एआइ और कंप्यूटर शिक्षा से जुड़ रहे हैं और एक दिव्यांग एडवोकेट शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बना रहे हैं। शाहजहांपुर से शुरू हुई पहल हो या माधव सेवा सोसायटी के माध्यम से वर्षों से चल रहा शिक्षण अभियान—ये दोनों उदाहरण साबित करते हैं कि संकल्प और सेवा से भविष्य की मजबूत नींव रखी जा सकती है।

समाज को शिक्षा के सहारे दिशा दे रहे दिव्यांग एडवोकेट विवेक जोशी

अंकित शर्मा • जागरण

जालंधर: किसी भी समाज की असली ताकत उसकी शिक्षा होती है। नेशनल अवार्ड प्राप्त एडवोकेट विवेक जोशी मानते हैं कि दिव्यांगता या आर्थिक कमजोरी शिक्षा की राह में बाधा नहीं बननी चाहिए। एक दशक से अधिक समय से समाज को सुशिक्षित करने की मुहिम में जुटे जोशी का मुख्य लक्ष्य ऐसा संवेदनशील समाज गढ़ना है, जहां प्रत्येक व्यक्ति पढ़-लिखकर अपने अधिकारों को समझे और आत्मनिर्भर बने।

इसी सोच को लेकर विवेक जोशी पिछले 11 वर्षों में एक हजार से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षित कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कई दिव्यांगों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई है और आर्थिक रूप से कमजोर व दिव्यांग छात्रों के केस निश्शुल्क लड़े। दिव्यांगजनों के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए वर्ष 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उन्हें सम्मानित कर चुके हैं।

जालंधर के बसंत हिल्स निवासी विवेक जोशी खुद सेरेब्रल पाल्सी (मस्तिष्क पक्षाघात) से ग्रस्त हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को समाज की ताकत में बदलने का रास्ता चुना। उनका मानना है कि जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक दिव्यांगों और कमजोर वर्गों के प्रति नजरिया नहीं बदलेगा। वर्ष 2014 में स्थापित माधव सेवा सोसायटी के माध्यम से उन्होंने शिक्षा को सेवा से जोड़ा। इस सोसायटी को कभी उन्होंने अकेले शुरू किया था, अब इससे 30 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें कई एडवोकेट, शिक्षक और उद्योगपति शामिल हैं।

सोसायटी से जुड़े बच्चों व सदस्यों के साथ विवेक जोशी (काली जैकेट में दाएं से पहले) • जागरण

एआइ और कंप्यूटर से शिक्षा पा रहे श्रमिकों व रिक्शा चालकों के बच्चे

अंबुज मिश्र • जागरण

शाहजहांपुर : राजमिस्त्री की बेटी रानी और रिक्शा चालक के बेटे आनंद...! पढ़ने की इच्छाशक्ति ने इन्हें स्कूल तक तो पहुंचा दिया, मगर सिर्फ किताबों से कौशल भला कैसे मिलता? ऐसे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की राह इंजीनियर राजीव अग्रवाल ने तैयार की। उन्होंने उत्तर प्रदेश के 147 स्कूलों में 30-30 कंप्यूटर की लैब स्थापित कीं, प्रत्येक में तीन-तीन प्रशिक्षक हैं। इनसे संबंधित सभी खर्च राजीव की संस्था फाउंडेशन फार एक्सीलेंस उठाती है। इन लैब में प्रशिक्षण पाने वाले 400 से अधिक बच्चों को एआइ, चैटजीटीपी की मदद से पढ़ाया जाता है। उन्हें एआइ, कोडिंग आदि का बेसिक ज्ञान दिया जाता है।

सिविल लाइंस निवासी राजीव अग्रवाल वर्ष 1985 में आइआइटी रुड़की से इंजीनियरिंग कर कुछ वर्ष बाद अमेरिका चले गए। वहां एमएक्यू साफ्टवेयर कंपनी बना ली। उनका समय-समय पर शाहजहांपुर आना होता है। वर्ष 2019 में उन्होंने आर्थिक कमजोर बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने का संकल्प लेते हुए फाउंडेशन फार एक्सीलेंस संस्था बनाई। फाउंडेशन के जिला समन्वयक भानु कुमार बताते हैं कि गुरुनानक कन्या पाठशाला, आर्य कन्या इंटर कालेज, आर्य महिला इंटर कालेज सहित जिले के 10 स्कूलों में कंप्यूटर लैब संचालित हो रही हैं। बच्चों को कंप्यूटर के अलावा खान एकेडमी की गणित व विज्ञान विषय भी आनलाइन पढ़ाया जाता है। इन बच्चों का चयन उनके स्कूलों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों के माध्यम से किया जाता है। अब तक जिले के 2,084 बच्चे चयनित हो चुके हैं।

कंप्यूटर लैब में छात्रों को एआइ, कोडिंग आदि का बेसिक ज्ञान दिया जाता है • जागरण

कौशल आधारित शिक्षा से सशक्त होंगे युवा

14.71 लाख स्कूलों की संख्या | **1.01** करोड़ शिक्षकों की संख्या | **24.69** करोड़ छात्रों की संख्या

सबको गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मुहैया कराना विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2025 लेकर आई है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विस्तार है। नई शिक्षा नीति भारत को कौशल उन्मुख और समावेशी शिक्षा प्रणाली की ओर ले जाने पर जोर देती है। प्रयास यह है कि छात्र सिर्फ किताब ज्ञान तक सीमित न रह कर जीवन के लिए आवश्यक कौशल भी सीखें। देश में प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और 19 लाख से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल रहा है। देश भर में पीएम श्री स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में एआइ के उपयोग से क्रांतिकारी बदलाव दिख रहे हैं। उम्मीद है कि 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की गति तेज होगी।

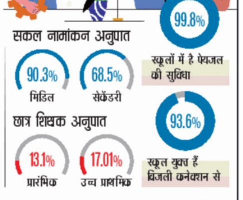

13,070 पीएम श्री स्कूल स्थापित किए गए हैं देश भर में पीएम श्री योजना के तहत

14,500 तक पहुंचानी है पीएम श्री स्कूलों की संख्या वित्त वर्ष 2026-27 तक

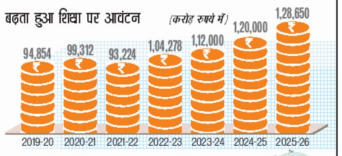

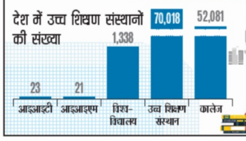

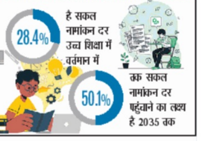

Dainik Jagaran Page No-7

> शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान देना नहीं है, बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करना है, जो सोच सकें। सही-गलत का विवेक रखें और अपने समाज व राष्ट्र को सकारात्मक दिशा देने में सक्षम हों।
>
> डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

दुनिया को अब भारत बताएगा एसआइआर के फायदे

सम्मेलन का आयोजन

दिल्ली में इस माह होने वाले एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में करीब 80 देश लेंगे हिस्सा, सम्मेलन में चुनाव सुधार व पारदर्शिता रहेगा अहम विषय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर विपक्षी दल भले ही चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन चुनावी विश्वसनीयता को बढ़ाने वाली भारतीय चुनाव आयोग की यह पहल जल्द ही दुनियाभर के देशों में भी देखने को मिल सकती है। चुनाव आयोग ने करीब दर्जनभर देशों की रुचि को देखते हुए अब इस पहल को चुनावी प्रबंधन निकायों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में साझा करने का फैसला लिया है। यह सम्मेलन 21 से 23 जनवरी के बीच नई दिल्ली में होने जा रहा है। जिसमें दुनिया के करीब 80 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

चुनाव आयोग से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, इस सम्मेलन के लिए अब तक करीब 50 देशों की सहमति भी मिल गई है। बाकी देशों की भी जल्द ही सहमति मिलने की संभावना है। इस बीच आयोग चुनावी विश्वसनीयता को मजबूती देने और मतदाता

सूची की विसंगतियों को दूर करने के लिए उठाए गए एसआइआर के कदम को इन देशों के साथ प्रमुखता से साझा भी करेगा। इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया के सामने खड़ी चुनौतियों पर भी इन देशों के बीच मंथन होगा। आयोग ने पिछले साल यानी जनवरी 2025 में भी ऐसा ही एक सम्मेलन आयोजित किया था। माना जा रहा है कि इस बार के सम्मेलन में और ज्यादा देशों की मौजूदगी रहेगी। आयोग ने यह पहल तब की है, जब दुनिया के अधिकांश देश चुनावी विश्वसनीयता और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों के जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत की मतदाता सूची को दुरुस्त करने की ये पहल सभी देशों को पसंद आ रही है।

सूत्रों के अनुसार, कुछ देशों के प्रतिनिधियों ने इसे लेकर जानकारी भी मांगी है। सम्मेलन में दुनियाभर के जो प्रमुख देश शामिल हो सकते हैं, उनमें फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, ब्राजील सहित इंटरनेशनल आइडीइए से जुड़े 37 सदस्यों देशों के साथ ही नेपाल, भूटान, श्रीलंका और रूसी संघ जैसे देशों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मौजूदा समय में इंटरनेशनल आइडीइए के अध्यक्ष भी हैं।

Dainik Jagaran Page No-3

बिहार कैलेंडर के प्रत्येक पन्ने पर दिख रही राज्य के विकास की तस्वीर

लोकार्पण

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को बिहार सरकार के जिस कैलेंडर का लोकार्पण किया है, उसके हरेक पन्ने पर राज्य के विकास की तस्वीर है। जनवरी के पृष्ठ पर सात निश्चय-3, उद्योगों के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाओं और मखाना का विशेष रूप से जिक्र है। इसी पृष्ठ पर ही सात निश्चय 3.0- प्रगति, विश्वास एवं जनकल्याण का निश्चय के तहत रोजगार और आय को बढ़ावा देने हेतु पहला निश्चय 'दोगुना रोजगार-दोगुनी आय', बिहार में औद्योगिक क्रांति हेतु दूसरा निश्चय 'समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार', किसानों की आय बढ़ाने के लिए तीसरा निश्चय 'कृषि में प्रगति-प्रदेश की समृद्धि', शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक एवं बेहतर बनाने हेतु चौथा निश्चय 'उन्नत शिक्षा-उज्ज्वल भविष्य आदि की चर्चा है।

फरवरी के पृष्ठ पर औद्योगिक विकास को केंद्र में रख निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाए जाने का जिक्र किया गया है। इसमें पहली बार मुफ्त जमीन और वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए महिला रोजगार जैसी विशेष योजनाएं चलाई गईं।

मार्च के पृष्ठ पर शिक्षा और कौशल विकास के जरिए शिक्षा से सशक्त, स्किल से समृद्ध युवा बिहार बनाने की दिशा में शिक्षा और कौशल विकास को बिहार ने भविष्य निर्माण की आधारशिला बनाए जाने की बात कही गई है। अप्रैल के पृष्ठ पर कहा गया है कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार के माध्यम से बिहार में रोजगार सृजन को विशेष प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य प्रशासनिक सेवाओं में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां कर युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया है। मई के पृष्ठ पर विज्ञान और प्रावैधिकी के तहत नवाचार और भविष्य निर्माण पर जोर दिया गया है। यह कहा जा रहा कि विज्ञान और प्रावैधिकी के क्षेत्र में बिहार में तकनीकी शिक्षा, नवाचार और डिजिटल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

जून के पृष्ठ पर सांस्कृतिक विरासत, बिहार की पहचान के तहत समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत वाला बिहार हिंदू, बौद्ध, जैन और सूफी परंपराओं की साझा धरोहर को सहेजते हुए संरक्षण और विकास दोनों को समान महत्व दिए जाने की बात कही गई है। वहीं, जुलाई के पृष्ठ पर कहा गया है कि ग्रामीण विकास, सशक्त पंचायत, प्रगतिशील बिहार के तहत बिहार के गांव विकास की नई पहचान बन रहे हैं। पक्की सड़कें, हर घर नल का जल, बिजली और कृषि योजनाओं ने ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाया है। इससे महिला सशक्तीकरण, युवाओं के रोजगार और किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है, जिससे राज्य आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।

अगस्त माह के पृष्ठ पर दर्ज है कि आधारभूत संरचनाओं के विस्तार, समृद्धि के नए आधार के तहत सुशासन और दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत बिहार ने विकास की नई रफ्तार पकड़ी है। सितंबर माह के पृष्ठ पर यह जिक्र है कि महिला सशक्तीकरण, आधी आबादी पूरा अधिकार के तहत बिहार में महिला सशक्तीकरण को विकास की आधारशिला बनाया गया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी नीति और व्यवहार दोनों स्तरों पर मजबूत हुई है। आरक्षण से हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

अक्टूबर माह के पृष्ठ पर यह कहा गया कि स्वस्थ बिहार का सपना साकार के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण ने बिहार को नई पहचान दी है। नवंबर माह के पृष्ठ पर खेल विभाग के अंतर्गत युवाओं के हौसलों की उड़ान के तहत बीते वर्षों में बिहार ने खेलों के क्षेत्र में लगातार प्रगति की है, इसका खास तौर पर जिक्र है। कैलेंडर के अंतिम पृष्ठ (दिसंबर माह) पर सुपर फूड मखाना, बिहार को दिला रहा वैश्विक पहचान का जिक्र किया गया है।

मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार डायरी और कैलेंडर का लोकार्पण किया। साथ में हैं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री विजय कुमार विजय कुमार चौधरी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव सह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार एवं निदेशक अनिल कुमार। • सौ : आइपीआरडी।

मुख्यमंत्री ने बिहार डायरी और कैलेंडर का किया लोकार्पण

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को बिहार डायरी और कैलेंडर का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प कक्ष में आयोजित हुआ। इस मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव सह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार, सचिव कुमार रवि, डा. चंद्रशेखर सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक अनिल कुमार भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जोखिम न्यूनीकरण कैलेंडर और टेबल कैलेंडर का भी लोकार्पण किया। लोकार्पण के अवसर पर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डा. उदयकांत, सदस्य पीएन राय, कौशल किशोर मिश्रा, प्रकाश कुमार, नरेंद्र कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, कुमार रवि, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा तथा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ सलाहकार डा. अनिल कुमार सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे।

Dainik Jagaran Page

सुविधा | 6जी तकनीक में मोबाइल टावर और सैटेलाइट दोनों से जुड़ पाएगा, आज जहां नो नेटवर्क आता है, वहां भी मोबाइल चलेगा

वर्ष 2030 तक आपका स्मार्टफोन सीधे सेटेलाइट से जुड़ सकेगा

बीजिंग, एजेंसी। मोबाइल फोन में नो नेटवर्क दिखना अब बीते दिनों की बात हो सकती है। पहाड़, जंगल, समुद्र या आपदा प्रभावित इलाकों में भी मोबाइल सिग्नल मिलने की उम्मीद है।

चीन और ब्रिटन के कुछ विश्वविद्यालयों सहित नए अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में पाया गया कि 2030 तक 6जी तकनीक और सेटेलाइट नेटवर्क मिलकर मोबाइल के नेटवर्क को हर जगह से जोड़कर इसकी पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। इस तकनीक के जरिए स्मार्टफोन सीधे आसमान में घूम रहे सेटेलाइट से जुड़ेंगे। इससे जमीन पर मोबाइल टावर न होने पर भी कॉल और इंटरनेट सेवा मिल सकेगी।

मस्क की कंपनी कर चुकी है साबित : एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स, एएसटी स्पेसमोबाइल और लिंक ग्लोबल जैसी कंपनियां फील्ड टेस्ट में यह साबित कर चुकी हैं कि सैटेलाइट से सीधे मोबाइल फोन को जोड़ने की तकनीक काम कर सकती है। स्पेसएक्स का स्टारलिंक तो 5,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। अब स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां भी अपने डिवाइस में सेटेलाइट चिप शामिल करना शुरू कर रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उन इलाकों तक नेटवर्क पहुंचाना है जहां मोबाइल टावर लगाना आर्थिक रूप से संभव नहीं है। साथ ही दूर-दराज क्षेत्रों, समुद्र में तथा आपदाओं के दौरान बनने वाले नो सर्विस जोन को कम करना है।

टावरों पर निर्भर: आज के मोबाइल नेटवर्क मुख्य रूप से जमीन पर लगे टावरों पर निर्भर हैं। लेकिन टावर हर जगह नहीं होता। दूर-दराज गावों में, समुद्र के बीच, पहाड़ी इलाकों, बाढ़ या तूफान वाले इलाकों में नो सर्विस जोन बन जाते हैं। 6जी का लक्ष्य है कि मोबाइल फोन सीधे सेटेलाइट से भी जुड़ सके। जिससे इन सभी जगहों पर भी नेटवर्क मिले और नो नेटवर्क की समस्या खत्म हो सके।

5000 से ज्यादा सेटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है स्टारलिंक

- 6जी वायरलेस नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क की छटी पीढ़ी है

सेटेलाइट ऐसे काम करते हैं

- 6जी नेटवर्क में लो-अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट पृथ्वी के करीब घूमते हैं
- आपका फोन जमीन के टावर के साथ सेटेलाइट्स से लिंक हो सकेगा
- फिर फोन तय करेगा कौन-सा स्रोत (टावर या सेटेलाइट) बेहतर नेटवर्क दे रहा है और खुद से जुड़ जाएगा
- यह ऐसा है कि यूजर को पता भी नहीं चलेगा कि नेटवर्क कहां से आ रहा है। सेटेलाइट से या जमीन से

ये देश 6जी की तैयारी में

- **चीन :** देश में 300 से ज्यादा 6जी तकनीकों पर काम हो रहा है
- **अमेरिका :** तकनीकी शोध और प्रयोगों में अग्रणी है।
- **जापान :** 6जी शोध और मानक निर्माण में सक्रिय है।
- **भारत :** भारत ने 6जी पेटेंट दाखिल करने में खुद को दुनिया के शीर्ष छह देशों में शामिल किया। देश में 6जी पर कई शोध चल रहे हैं।

Hindustan Page- 15

बाइबिल का रहस्यमयी कोड दो हजार साल बाद पढ़ा गया

एम्स्टर्डम, एजेंसी। करीब 70 सालों के इंतजार के बाद वैज्ञानिकों ने 'डेड सी स्क्रॉल' की एक पुरानी पांडुलिपि 'क्रिप्टिक बी' को डिकोड कर लिया है।

ये प्राचीन दस्तावेज 2,000 साल पुराने हैं, जिन्हें लंबे समय से पढ़ना असंभव माना जा रहा था, क्योंकि इनकी लिखावट अजीब और कोड भाषा में थी। नीदरलैंड के ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ता इन कोड को हिब्रू भाषा के अक्षरों से जोड़कर इनका अर्थ निकाला है। इनमें इजराइल, भगवान और याकूब जैसे शब्दों का जिक्र है। साथ ही, इनमें दुनिया के अंत, ईश्वर के न्याय और आने वाले मसीहा के बारे में भविष्यवाणियां लिखी गई हैं।यह खोज इसलिए खास है क्योंकि ये पांडुलिपियाँ दुनिया के सबसे पुराने जीवित धार्मिक ग्रंथों में से हैं। इनसे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि 2,000 साल पहले लोग धर्म और भविष्य को लेकर क्या सोचते थे।

Hindustan Page- 18

देश के सभी राज्यों में सर्वे के बाद ब्योरा तैयार किया जाएगा

तंबाकू खाने वाले युवाओं का राज्यभर में सर्वे होगा

एक्सक्लूसिव

■ मृत्युंजय

मुजफ्फरपुर। बिहार सहित पूरे देश में कितने युवा तंबाकू खा रहे हैं, इसका सर्वे कराया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यह सर्वे कराएगा। इसका नाम 'ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे' रखा गया है। इसके लिए मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को निर्देश जारी किया गया है।

मंत्रालय के निर्देश के बाद राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को सर्वे कराने के लिए पत्र लिखा है। स्वास्थ्य विभाग के गैर संचारी रोग कार्यक्रम के तहत यह सर्वे कराया जाएगा। मुजफ्फरपुर के एनसीडीओ डॉ. नवीन कुमार का कहना है कि इस सर्वे से युवाओं में तंबाकू की लत छुड़ाने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस सर्वे में आठवीं से दसवीं तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें। बच्चे इस अभियान के ब्रांड एंबेसडर बनाए जाएंगे, ताकि वे स्कूलों में जो बच्चे तंबाकू खाते हैं, उनकी लत छुड़ा सकें। उन्हें इसके सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तास से बता सकें।

08 वीं से 10वीं तक के बच्चे होंगे शामिल

- ■ राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सर्वे के लिए सभी जिलों को दिया निर्देश
- ■ एनसीडीसी को मिला निगरानी का जिम्मा, सभी राज्य भेजेंगे रिपोर्ट

सर्वे से जाना जाएगा तंबाकू उपयोग का पैटर्न

राज्यों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि इस सर्वे का मकसद देशभर में तंबाकू उपयोग के पैटर्न को जानना है। यानी, युवा तंबाकू की श्रेणी में आने वाले किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सर्वे के बाद देश में तंबाकू नियंत्रण के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। मंत्रालय ने इस कार्यक्रम की निगरानी का जिम्मा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) को दिया है। देश के सभी राज्य अपनी रिपोर्ट एनसीडीसी को सौंपेंगे।

इसके अलावा कॉलेजों में भी यह सर्वे किया जाएगा। खासतौर पर वैसे युवाओं पर फोकस किया जाएगा जो इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। इसके लिए राज्य के 69 स्कूलों का चयन किया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में मुशहरी के एक स्कूल का चयन हुआ है।

मुजफ्फरपुर में बंद हुआ तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम : मुजफ्फरपुर जिले में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम ठप हो गया है। डेढ़ साल पहले तंबाकू नियंत्रण के तहत काम करने वाली काउंसलर के इस्तीफे के बाद राज्य सरकार ने जिले में दूसरे काउंसलर की नियुक्ति नहीं की। काउंसलर का काम स्कूलों और अन्य जगहों पर जाकर लोगों, युवाओं और छात्रों को तंबाकू की हानियों के बारे में बताना था। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम भी स्वास्थ्य विभाग के गैर संचारी रोग (एनसीडी) के तहत ही चलता है। हालांकि, एनसीडीओ डॉ. नवीन का कहना है कि वह एक डॉक्टर से लोगों की काउंसिलिंग करा रहे हैं। लोगों को इशसे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में भी सभी को जानकारी दी जा रही है। इसके अवाला काउंसिलिंग भी की जा रही है।

सदर अस्पताल के अलावा एसकेएमसीएच में भी तंबाकू नियंत्रण केंद्र सुपर स्पेशियलिटी में खोला गया था, लेकिन वहां इसको लेकर कोई काम नहीं हो रहा है।

बिहारशरीफ से दनियावां के लिए पिंक बस शुरू

बिहारशरीफ सरकारी बस स्टैंड में गुरुवार को पिंक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते मंत्री श्रवण कुमार व अन्य।

बिहारशरीफ, निज संवाददाता। नए साल के पहले दिन नालंदा की आधी आबादी को सुरक्षित सफर का नायाब तोहफा मिला है। महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए दो पिंक बसों की सेवा शुरू हो गयी है।

बिहारशरीफ सरकारी बस स्टैंड में गुरुवार को मुख्यंत्री नीतीश कुमार की माता स्व. परमेश्वरी देवी की पुण्यतिथि पर दोनों पिंक बसों को हरी झंडी दिखाकर परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने रवाना किया। दनियावां के लिए दो तो बरबीघा के लिए तीन बार बसें खुलेंगी। फिलहाल कमान पुरुष ड्राइवर के हाथ में दी गयी है। जबकि, महिला कंडक्टर टिकट काटेंगी। अप्रैल से दोनों की महिला कर्मी बसों का संचालन करेंगी। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि 2026 में बिहार की बसें विदेशों तक दौड़ेंगी। इसके साथ ही, जल्द ही और नई इलेक्ट्रिक बसों का भी परिचालन किया जाएगा। ये बसें पूरी तरह से सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। एक बिहारशरीफ से दनियावां के लिए चलेंगी। यह दिनभर में दो फेरे यानि दो बार अप और डाउन करेगी।

कहां से कब खुलेंगी

बिहारशरीफ से बरबीघा : 6.00 बजे सुबह, 10.00 बजे, 2.00 बजे

बरबीघा से बिहारशरीफ : 8.00 बजे सुबह, 12.00 बजे, 16.00 बजे

बिहारशरीफ से दनियावां : 6.00 बजे सुबह, 1.00 बजे

दनियावां से बिहारशरीफ : 10.30 बजे, 05.30

Hindustan Page No-12

बड़े-बुजुर्गों में टीकाकरण की अहमियत समझना जरूरी

नए साल के सेहत संकल्पों में अक्सर भोजन, व्यायाम और तनाव प्रबंधन की चर्चा होती है। इस कड़ी में बड़ों में टीकाकरण को शामिल करना कितना जरूरी है, बता रहे हैं रुमेटोलॉजिस्ट डॉ. श्यामाशीष बंद्योपाध्याय

बहुत से लोग मानते हैं कि टीके केवल बच्चों के लिए होते हैं। हालांकि, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने लगती है, जिससे हम संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। वयस्कों में टीकाकरण लंबे समय तक स्वस्थ रहने का प्रभावी और सरल उपाय है। इससे सेहत समस्याओं को गंभीर होने से बचा जा सकता है। इसके तीन कारण हैं-

1. मौसमी संक्रमण

इन्फ्लुएंजा, फ्लू जैसे मौसमी संक्रमण सामान्य लग सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये बेहद गंभीर हो सकते हैं। 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, मधुमेह, सीओपीडी व हृदय रोग जैसी स्थितियों के साथ जी रहे लोगों में रोगों के गंभीर होने और अस्पताल में भर्ती होने की आशंका अधिक होती है।

फ्लू की एक बार चपेट में आना हफ्तों तक चलने वाली कमजोरी, सांस फूलने और थकान का कारण बन सकता है। इससे लोगों की सक्रियता कम होने लगती है। रोज के काम करना कठिन हो जाते हैं और दूसरों पर निर्भरता बढ़ जाती है। फ्लू के वायरस हर साल बदलते हैं, इसलिए टीके की दवा भी बदल जाती है। समय पर टीकाकरण बुजुर्गों को सक्रिय रहने, अस्पताल के चक्करों से बचने में मदद करता है।

2. परिवार का भी बचाव

एक संक्रमण जो परिवार के एक सदस्य में हल्के लक्षण पैदा करता है, वह दूसरे के लिए गंभीर हो सकता है। खासकर शिशुओं, गर्भवती महिलाओं या कमजोर प्रतिरक्षा वाले बुजुर्गों में संक्रमण गंभीर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 'शिंगल्स' स्वयं संक्रामक नहीं है, लेकिन इसका वायरस उन लोगों में चिकनपॉक्स का कारण बन सकता है, जिनकी प्रतिरक्षा कम है। यह बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। बुजुर्गों में टीकाकरण को बढ़ावा देना परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए भी सुरक्षा कवच बन सकता है।

3. पुरानी बीमारियों पर बना रहे काबू

किसी पुरानी बीमारी के प्रबंधन के लिए निरंतर ध्यान, दवा और जीवनशैली में बदलाव की जरूरत होती है। जब फ्लू या शिंगल्स जैसे संक्रमण होते हैं, तो पुरानी स्थितियां काबू रखने में दिक्कत आती है। जैसे फ्लू से दमा का दौरा बढ़ सकता है या हृदय की स्थिति बिगड़ सकती है। वहीं, मधुमेह के रोगियों में शिंगल्स के कारण ब्लड शुगर अचानक बढ़ सकता है, भले ही वे अपना उपचार सही ढंग से ले रहे हों।

अध्ययन बताते हैं कि संक्रमण से शरीर में सूजन और तनाव बढ़ता है। नियमित टीकाकरण संक्रमण के जोखिम को कम करता है। साथ ही एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत भी कम हो जाती है।

Hindustan Page No-11

अनुलोम-विलोम

विपक्ष

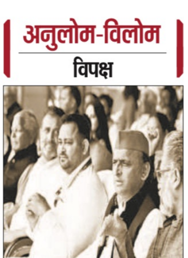

विपक्षी दलों पर लोगों को भरोसा नहीं

लोगों को विपक्षी दलों पर किंचित भी भरोसा नहीं। किसी मनोवैज्ञानिक से दरयाफ्त करें, कहीं यह खुद पर अविश्वास का सूचक तो नहीं! अमूमन लोग दूसरों के बारे में वैसी ही धारणा बनाते हैं, जैसे खुद होते हैं। मनुष्य की अपनी मानसिक सीमा होती है। मामला यहीं तक सीमित होता, तब भी कोई बात थी। बात आगे बढ़ गई है। थोड़ा सच और ढेर सारा झूठ मिलाकर ऐसे गैर-जिम्मेदाराना आरोप गढ़ लेना, जिनकी कल्पना भी सामान्य आदमी के जेहन में कठिन है। हो सकता है, ऐसा करते समय वे अपनी ही (आपराधिक) मानसिकता का परिचय दे रहे हों। उनकी कल्पना में वही आता हो, जो ऐसी स्थिति में वे खुद करते।

सब्र और जिम्मेदारीपूर्ण आलोचना तो भारतीय जनतंत्र की शब्दावली से हटा ही देनी चाहिए। फेसबुक पर भी ऐसे ही गैर-जिम्मेदार और सच-झूठ की मिलावट से निःसृत कुत्सित आरोपों से भरी पोस्ट बहुतायत में दिख जाएंगी। जैसे निखालिस इसी एजेंडे के तहत सोशल मीडिया पर अवतरित हुए हों। मगर सबसे खतरनाक पहलू दूसरा है। मीडिया-वर्चस्व के इस युग में सामान्य जनता राजनीतिक दलों से सीधे प्रभाव ग्रहण करती है। उनके नेताओं का विचलन सामान्य जनता के विचलन को आश्वस्ति प्रदान करता है। पूरे देश की चारित्रिक गिरावट का पूरा सरंजाम मौजूद है। विपक्ष की हताशा देखकर लगता तो यही है कि बेहतर विकल्प देने की सारी संभावनाएं खर्च हो चुकीं। अब तो यही कहा जाएगा कि सत्ता पक्ष जाएगा, तो अपने ही 'कर्मों', अंतर्विरोधों व कदाचारों से जाएगा। विपक्ष के बूते की बात नहीं कि उसे टस से मस कर सके।

हाल में बिहार में उन्मत्त और बेलगाम घोड़ों (मोटर साइकिलों) पर सवार युवा सेनानियों ने ऐसा समां बांधा कि लगा, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय का बिहार अंगड़ाई ले रहा है और बस जागने ही वाला है, मगर ढाक के वही तीन पात। 'एसआईआर' न हुआ, ब्रह्मास्त्र हो गया।

अब वही दंगल पश्चिम बंगाल में चलने वाला है। वहां एक अजेय वीरांगना का सेनापतित्व है और 'इंडिया' ब्लॉक के नामचीन और अनाम घटकों की सेनाओं का जमावड़ा। तलवारें खिंच गई हैं। उधर सीमा पार के देश में सत्ता-सदनों पर हमले आयोजित हो रहे हैं, जबकि वहां की दो वीरांगनाएं- तस्लीमा नसरीन और शेख हसीना- किसी तरह जान-बचाकर भारत की शरण में हैं। जरूरत पड़े, तो स्वयं की जान देकर शरणागत की रक्षा करना हमारा परंपरागत और परम धर्म है। जो भी हो, बंगाल का चुनाव-परिणाम हमारे विपक्षी दलों के महान गठबंधन की अग्नि-परीक्षा है, और भारत के राजनीतिक भविष्य का पूर्वराग भी।

कमलाकांत त्रिपाठी, टिप्पणीकार

सत्ता पक्ष को विपक्ष ने लगातार घेरा

आज के समय में विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस को लेकर एक निराशावादी माहौल बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया व कुछ राजनीतिक हलकों में कांग्रेस को कोसना और राहुल गांधी का उपहास उड़ाना मानो फैशन बन गया है। कहा जाता है कि कांग्रेस खत्म हो रही है, पर वास्तविकता इससे पूरी तरह अलग है। कांग्रेस को कोसने या राहुल गांधी का मजाक उड़ाने से कोई राजनीतिक सत्य सिद्ध नहीं होता; बल्कि यह इस बात का संकेत है कि कांग्रेस की विचारधारा और विपक्ष की भूमिका से कुछ लोग असहज हैं।

सच यह है कि 2014 और 2019 की करारी हार के बाद, जब कांग्रेस संगठनात्मक रूप से टूटने के कगार पर थी, तब राहुल गांधी ने पार्टी को पूरी तरह छोड़ा नहीं। 'भारत जोड़ो यात्रा' जैसे अभियानों के माध्यम से उन्होंने हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आम जनता से संवाद स्थापित किया और कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीतकर 2019 की तुलना में अपनी ताकत दोगुनी की। 'इंडिया' ब्लॉक ने भाजपा को पूर्ण बहुमत से रोका। यह लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने और उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, जाति जनगणना, सामाजिक असमानता, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर सरकार को लगातार घेरा।

निश्चय ही कांग्रेस के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। 2024 के बाद कुछ राज्यों में चुनावी हार, संगठन के भीतर मतभेद और भाजपा की सशक्त चुनावी मशीनरी के सामने संसाधनों की कमी- ये सभी वास्तविक समस्याएं हैं। पार्टी को युवाओं, महिलाओं और हाशिये पर खड़े वर्गों से और गहरे जुड़ने की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर उसे अधिक स्पष्ट और आक्रामक रणनीति अपनानी होगी। इतिहास गवाह है कि यह पार्टी विभाजन, आपातकाल, 1984 की त्रासदी और 2014 व 2019 की पराजय जैसे अनेक संकटों से उबर चुकी है, और हर बार उसने स्वयं को पुनर्गठित किया है। कांग्रेस को कोसने वाले यह भूल जाते हैं कि एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की रीढ़ होता है। सत्ता से सवाल पूछना, नीतियों की समीक्षा करना और वैकल्पिक दृष्टि पेश करना- यही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। कांग्रेस आज भी जीवित है, क्योंकि वह जनता से जुड़ने का प्रयास कर रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रही है। यह मैं लोकतंत्र समर्थक होने के नाते कह रहा हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि किसी भी देश में लोकतंत्र तभी मजबूत होता है, जब सत्ता के साथ-साथ विपक्ष भी मजबूत हो।

राकेश पाण्डेय, टिप्पणीकार

Hindustan Page No-10

इंदौर से सबक

देश के सबसे स्वच्छ शहरों में वर्षों से शिखर पर रहे इंदौर में दूषित पेयजल की वजह से अनेक लोगों की मौत बहुत दुखद और चिंताजनक है। लगभग 150 लोग दूषित पेयजल की वजह से अस्पतालों में भर्ती हैं। यह एक ऐसी त्रासद घटना है, जिसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव ने आपातकालीन स्थिति बताया है। न्यायालय ने भी संज्ञान लेकर यथोचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। चौतरफा आलोचनाओं के बीच राज्य सरकार ने आपातकालीन उपाय तेज कर दिए हैं, लेकिन यह समस्या ऐसी है कि जिसका स्थायी उपाय करने की जरूरत है। एक आरोपी अधिकारी को बर्खास्त किया गया है, तो दो को उचित ही निलंबित किया गया है। इंदौर के इस हादसे से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इस एक हादसे ने देश के तमाम शहरों में लोगों को चिंता में डाल दिया है। देश के सबसे स्वच्छ शहर में अगर लोगों को जहरीला पानी मिल सकता है, तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा? दूषित जल से नुकसान का सही आकलन करना जरूरी है। करीब 80 प्रतिशत बीमारियों और एक तिहाई मौतों के पीछे दूषित जल ही दोषी है। हालांकि, हमें यह भी देखना होगा कि दूषित जल के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं?

अभी जो तथ्य सामने आए हैं, उनके अनुसार, सीवेज लाइन में रिसाव था और वह जलापूर्ति लाइन से होकर गुजर रही थी। यह अपनी तरह का कोई पहला मामला नहीं है। ऐसा अनेक जगहों पर हुआ है और समय रहते समाधान के उपाय भी किए गए हैं। दरअसल, जहां लोग जागरूक हों और स्थानीय निकाय अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाता हो, वहां दूषित आपूर्ति को रोकना आसान है। इंदौर में ऐसा हो सकता है कि दूषित जल पर देर से ध्यान गया हो। खैर, इंदौर में ऐसे अनेक सवाल खड़े हुए हैं, जो देश के दूसरे शहरों पर भी लागू होते हैं। क्या पेयजल की गुणवत्ता का परीक्षण नियमित रूप से किया जाता है? क्या पेयजल की गुणवत्ता में आ रहे बदलावों पर नजर रखी जाती है? क्या यह देखा जाता है कि जलापूर्ति तंत्र या सीवेज तंत्र कितना पुराना हो गया है? ऐसे तंत्र की आयु कितनी होती है? कितने साल या दशक के बाद इस तंत्र का नवीनीकरण करना चाहिए? इंदौर की दुखद घटना साफ संकेत है कि देश के अच्छे शहरों में भी जलापूर्ति तंत्र को तत्काल ठीक करने की जरूरत है। जहां लाइनें पुरानी पड़ गई हैं, वहां तत्काल प्रभाव से नवीनीकरण होना चाहिए। आज जिस दौर में हम हैं, वहां गांव हो या शहर, हम कभी भी पेयजल गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकते। यह देश के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, जिसमें निवेश बढ़ाना देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है।

करीब 80 प्रतिशत बीमारियों और एक तिहाई मौतों के पीछे दूषित जल ही दोषी है। हालांकि, हमें यह देखना होगा कि दूषित जल के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं?

इंदौर में दूषित जल के सेवन के बाद लोगों को उल्टी, दस्त और निर्जलीकरण की शिकायत हुई है। अब समय आ गया है, जब शौचालय तंत्र और जलापूर्ति तंत्र को एक-दूसरे से बिल्कुल अलग रखा जाए। यह एक सामान्य जागरूकता की बात है कि यदि किसी जल से किसी भी प्रकार की दुर्गंध आए, तो उसके सेवन से हर हाल में बचना चाहिए। यह सावधानी आसान नहीं, लेकिन इसे सुनिश्चित करना होगा। मोटे अनुमान के अनुसार, 70 प्रतिशत से ज्यादा भारत में व्यवस्थित सीवेज तंत्र का अभाव है। अगर देश में 70 एमएलडी दूषित जल पैदा होता है, तो उसमें से महज 30 एमएलडी जल के शोधन की क्षमता है। बगैर-शोधन के जब दूषित जल मिट्टी में मिलता है, तो जाहिर है, जल व मिट्टी, दोनों की हानि होती है। इंदौर जैसे कथित स्वस्थ शहर में खतरे की एक घंटी बजी है और यह पूरे देश के जागने का समय है।

बिहार के शूटिंग लोकेशन आसानी से खोजे जा सकेंगे

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। विश्व के किसी भी कोने से बिहार के शूटिंग लोकेशन को अब आसानी से खोजा जा सकता है। यह बिहार स्टेट फिल्म विकास निगम की वेबसाइट से संभव हो सका है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत एवं वित्त विभाग की सचिव रचना पाटिल ने गुरुवार को निगम की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया।

कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार ने कहा कि यह वेबसाइट बिहार के सभी शूटिंग स्थलों को अत्यंत प्रभावी एवं आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करती है, जिससे उपयोगकर्ता को वास्तविक अनुभव की अनुभूति होती है। इस वेबसाइट से उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरों के जरिये बिहार के शूटिंग लोकेशन को आसानी से खोजा जा सकता है। श्री कुमार ने बताया कि इस वेबसाइट पर राज्य के कलाकारों का विस्तृत विवरण है। साथ ही यह वेबसाइट एक ऐसा इकोसिस्टम प्रदान करती है, जिससे विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।

> ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा मूल मंत्र है और वर्ष 2026 तक बड़े डिजिटल रिफॉर्म के लक्ष्य की दिशा में यह वेबसाइट निश्चित रूप से एक सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण कदम है।
>
> **-प्रत्यय अमृत,** मुख्य सचिव

Hindustan Page No-2

प्रेरणादायक | विश्वविद्यालयों-कॉलेजों के परियोजना कार्य में बिहार की जीविका दीदियों की कहानी शामिल, सोशल स्टडी, एमबीए व अर्थशास्त्र के विद्यार्थी जीविका समूहों की सफलता जान रहे

जीविका दीदियों के संघर्ष को जानेंगे सात राज्यों के विद्यार्थी

पटना, मुख्य संवाददाता। गरीबी दूर करने को जीविकापार्जन की तरफ बढ़ना, पुस्तैनी या पसंद के रोजगार शुरू करना। इसके लिए प्रशिक्षण लेना। छोटी पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू करना। फिर समूह से जुड़कर लोन लेकर कारोबार को बढ़ाना। कारोबार बढ़ने पर खुद की कंपनी खोलना।

जीविका दीदियों के जीविकापार्जन के संघर्ष को जानने देशभर के छात्र और छात्राओं की टीम बिहार आ रही है। देश के सात राज्यों के विवि और कॉलेजों ने अपने परियोजना कार्य (प्रोजेक्ट वर्क) में जीविका दीदियों को शामिल किया है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राज्य शामिल है।

विवि और कॉलेजों की टीम बिहार के अलग-अलग गांवों में जाकर जीविका दीदियों से मिलकर उनके लखपति बनने तक की जानकारी लेकर प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। मालूम हो कि विभिन्न विवि और कॉलेजों ने सोशल स्टडी, एमबीए, अर्थशास्त्र विषय में ग्रामीण महिलाओं के जीविकोपार्जन को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। चूंकि बिहार की जीविका दीदी देशभर की आजीविका में सबसे ऊपरी पायदान पर है। यहां की जीविका दीदी अन्य राज्यों में जाकर ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण भी दे रही है। ऐसे में यहां की जीविका दीदियों के संघर्ष और आगे बढ़ने की कहानी को प्रोजेक्ट वर्क में शामिल किया जाता है।

सरस मेले में भी छात्राओं की कई टीमें पहुंचीं : विभिन्न राज्यों के विवि और कॉलेजों की टीम सरस मेला में भी दीदियों से मिलने आ रही है।

गांधी मैदान में लगे सरस मेला में महाराष्ट्र विवि की तीन टीम विभिन्न स्टॉल पर जाकर जीविका दीदियों से मिलकर उनके जीविकापार्जन की जानकारी ली। इसके अलावा गुजरात, असम और राजस्थान की टीम भी अलग-अलग दिन सरस मेला पहुंची। सरस मेला नहीं रहने पर जीविका प्रशासन से संपर्क कर छात्रों की टीम गांव में जाकर जीविका दीदियों से मिलती है। वर्ष 2025 में 15 से 20 कॉलेजों के छात्रों की टीम जीविका दीदियों पर अपना प्रोजेक्ट तैयार कर चुके हैं।

15 से 20 कॉलेजों की टीम बिहार के अलग-अलग गांवों में जाकर जीविका दीदियों से मिल रही

इन राज्यों की टीमें आई हैं : महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश

> जीविका दीदियों के संघर्ष को जानने और समझने के लिए कई राज्यों के छात्रों की टीम आती है। इनके विवि या कॉलेजों ने परियोजना कार्य में ग्रामीण महिलाओं के जीविकापार्जन को शामिल किया है। टीम बिहार की ग्रामीण महिलाओं से जानकारी लेने आते हैं। वे जीविकापार्जन को जानते हैं और प्रोजेक्ट तैयार करते हैं।
>
> **-हिमांशु शर्मा, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,** जीविका बिहार

ये जानकारी ले रहे छात्र

- गांव में रहकर काम करने की रुचि कैसे पैदा हुई
- एक हजार से काम शुरू कर सफल उद्यमी कैसे बनीं
- लखपति दीदी बनने के लिए किसने प्रेरित या प्रोत्साहित किया
- लोन लेकर व्यवसाय को आगे कैसे बढ़ाया
- गांव से शहर में आकर उत्पाद की बिक्री में क्या परेशानी होती है
- कम पढ़ी लिखी जीविका दीदी आगे स्नातक की पढ़ाई करने की जरूरत क्यों पड़ी

Hindustan Page No-2

Useful For Mains

वक्त का हिसाब

अनिता वर्मा

अभिनंदन और विदाई- ये सब जीवन यात्रा के अभिन्न अंग है। जनवरी से दिसंबर के महीने के बीच जो भी घटित होता है, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, घर-परिवार, देश-विदेश से लेकर सृजन साहित्य तक, वह सब समय के साथ अपनी अवधि के भीतर घटित होकर अपने पद चिह्न मन-मस्तिष्क पर छोड़ जाता है। अमूमन हर बीता वर्ष इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होता है। हर बार के आकलन में हम गौर करते हैं कि वैश्विक पटल पर कई घटनाक्रम हुए, जो सब कुछ समय के साथ अपना निर्धारित स्थान इस वर्ष में दर्ज करवा कर इस वर्ष में स्थायी हो गए। खेल, साहित्य, शिक्षा और तकनीक में कई उपलब्धियों ने हमें समृद्ध किया और हम सबका गौरव बढ़ाया। व्यक्तिगत संदर्भों में कई मित्र जुड़े, कई बिछड़ गए। यह जीवन का हिस्सा रहा। समय का अभाव कहें या परिस्थितियां, सबके साथ हम चलते रहे। हम सब अपने भीतर झांक सकते हैं कि इस सबके बीच कई बार द्वंद्व रहा, उलझनें रहीं तथा समस्याएं और समाधान साथ-साथ चलते रहे।

समय की धारा में हम सब बहते चले जाते हैं, क्योंकि समय बलवान होता है। समय को हम चाह कर भी पकड़ नहीं पाते। बल्कि यों कहें कि नहीं पकड़ सकते। समय अदृश्य है, पर चलता रहता है अनवरत। यों भी, यह किसी के रोके कभी रुका है क्या? रोकने की कोशिश करने वाले लोग रुक गए, लेकिन समय चलता रहा। हम समय के अभाव का रोना रोते रहते है और समय अपनी निर्धारित सीमा में अपनी चाल चलता रहता है। गांव, शहर, गलियां, व्यक्ति आदि जाने क्या-क्या अपने नवीन संदर्भों के साथ जुड़ते और छूटते चले जाते हैं। हम चुपचाप समय के साथ अपने दिन व्यतीत करते जाते हैं। समय की धारा में हर्ष, विषाद, सम्मान, पुरस्कार, अभिनंदन, सफलताएं, असफलताएं... और भी न जाने क्या हमारे जीवन का हिस्सा बन कर कभी हमें आनंद के सागर में डुबो देते हैं और कभी निराशा हमारा दामन पकड़ कर पीछे खींचती है। मगर हमारा आत्मविश्वास हमें समय के साथ कदमताल मिलाता आगे ले जाता है।

दुनिया मेरे आगे

> समय की धारा में हम सब बहते चले जाते हैं, क्योंकि समय बलवान होता है। समय को हम चाह कर भी पकड़ नहीं पाते। समय अदृश्य है, पर चलता रहता है अनवरत। रोकने की कोशिश करने वाले रुक गए। हम समय के अभाव का रोना रोते हैं और समय अपनी निर्धारित सीमा में अपनी चाल चलता रहता है।

यही आत्मविश्वास मन के भीतर ऊर्जा, उत्साह, उमंग का संचार करता है। एक नई सुबह रोज बांह पसारे सुंदर मुस्कान के साथ हमारा स्वागत करती है। हम पिछला सब कुछ भूल कर फिर से नए दिन के सूरज के साथ अपने कार्यों में तल्लीनता से संलग्न हो जाते हैं। यही हमें जीवंत बनाए रखता है। बीते वर्ष के दिसंबर ने अब हमसे विदाई ले ली है। जैसे-जैसे हम चिंतन करते हैं इस तरह की विदाई के बारे में, अचानक हम सबके मुंह से निकलता है कि पिछले दिसंबर के बाद भी नया साल आया था और अब फिर यह पूरा हो गया। नया वर्ष अपनी नवीन रूपरेखा, नवीन गतिविधियों उपलब्धियों के साथ दस्तक दे चुका है। पता ही नहीं चला कि बीता वर्ष भी कैसे चुपके से बीत गया। बहुत कुछ नया जुड़ा, बहुत कुछ पुराना पीछे छूट गया। कई सुखद क्षणों में आनंददायी पलों को जिया और कभी मन अनेक बार विपरीत परिस्थितियों में व्याकुल हुआ... आंखें नम हुईं। क्या यही सब फिर से इस वर्ष हमारे जीवन में नहीं दुहराएगा?

दरअसल, ये सब जीवन के अहम हिस्से हैं। इनके सहारे ही जीवन समय के साथ गतिमान रहता है। जीवन चलने का नाम है। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में लिखा है- 'दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक परदा नीला झीन छिपाए है जिसमें सुख गात।' वक्त के साथ हम सब पिछले बीत चुके महीनों का हिसाब-किताब लगाते हैं। किसी की झोली में खुशियों के दीप जगमगाते हैं, तो किसी के हिस्से में आया दर्द उसे भीतर तक हिला देता है। कभी उम्मीद खिल जाती है, तो कभी भय का साया मंडराने लगता है कि क्या दर्द का सिलसिला कायम रहेगा। फिर भी समय तो समय है, जैसा भी हो बीत ही जाता है। समय सब कुछ भर देता है।

सुख-दुख जीवन के दो पहलू हैं, जिनके साथ हम सबको अपनी-अपनी भूमिकाएं निभानी पड़ती है। समय किसी के रोकने से नहीं रुकता, जैसे देखते-देखते पिछला वर्ष बीत गया और अब नए वर्ष का सफर शुरू हो चुका है। कितना कुछ पीछे छूट जाता है। हम सब स्मरण करते हैं कि कल की ही तो बात है कि हमने इस वर्ष के स्वागत के लिए पलक-पांवड़े बिछाए थे। अब वह भी चला गया। हम फिर नव ऊर्जा के साथ तैयार हो जाते हैं नववर्ष के स्वागत अभिनंदन के लिए और बीते वर्ष को विदाई देने। यही सृष्टि का नियम भी है।

नूतनता सदैव वंदनीय अभिनंदनीय होती है। जीवन के विविध क्षेत्रों में जहां हमारी उपस्थिति है, वह सब बीते वर्ष के बही खाते में दर्ज हो जाता है। इसके बाद तो कैलेंडर के पन्ने और तिथियां बदल जाती हैं। कभी-कभी ऐसा अहसास होता है कि कितनी तेजी से समय भाग रहा है। एक वर्ष जीवन का और बीत चला अपने पीछे कितने स्मृति-चिह्न छोड़ता हुआ। कितना कुछ रह-रहकर याद आता है लोगों के साथ बिताया गया समय। वे खिलखिलाते चेहरे, वे शहर, वे जगहें, जहां हम घूमने या किसी विशेष कारण से गए, वे यात्राएं, यात्राओं के सहयात्री, यात्राओं के अविस्मरणीय पल..! कुछ भी भूल नहीं पाते, भले ही पुराना साल बीत गया हो। समय की अपनी अवधि और सीमाएं- इन सबके बीच संघर्षशील व्यक्ति गतिमान रहता है।

अरावली के संरक्षण की मुश्किल राह

अरावली कई दशकों से मानवीय दबाव झेल रही है। पत्थर और चूना-पत्थर की निरंतर निकासी ने कई पहाड़ियों को कमजोर कर दिया है। जंगलों का नुकसान हुआ है। आसपास के शहरों में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती गई है।

देवेंद्रराज सुथार

अरावली पर्वत श्रृंखला एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। इस बार बहस का कारण केवल खनन नहीं, बल्कि वह नई न्यायिक स्थिति है जो सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद बनी है। न्यायालय ने बीते 20 नवंबर के अपने आदेश पर रोक लगाते हुए यह स्पष्ट किया है कि 21 जनवरी 2026 तक अरावली क्षेत्र में खनन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके साथ ही एक नई उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है, जो पहले से नियुक्त समिति की रपट तथा न्यायालय की टिप्पणियों का स्वतंत्र और निष्पक्ष मूल्यांकन करेगी। न्यायालय ने यह भी कहा है कि पिछली सिफारिशें और उन पर आधारित उसकी टिप्पणियां फिलहाल स्थगित रहेंगी और अगली सुनवाई तक लागू नहीं की जाएंगी। पहली नजर में यह निर्णय सावधानी भरा, संतुलित और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विचारणीय कदम प्रतीत होता है। न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि कोई भी व्यवस्था लागू होने से पहले उसका वैज्ञानिक, सामाजिक और कानूनी परीक्षण अवश्य हो।

फिर भी यह सवाल कायम है कि इतनी स्पष्टता के बाद भी अरावली पर विवाद और विरोध क्यों जारी है। इसका उत्तर उस गहरी दूरी में छिपा है जो नीति के इरादों और उसके व्यावहारिक क्रियान्वयन के बीच बनी रहती है। कई लोगों को डर है कि यदि निगरानी और प्रवर्तन कमजोर रहा, तो कोई भी नई व्यवस्था केवल कागजों में सुशोभित होकर रह जाएगी, जबकि जमीन पर पुराने ढर्रे ही चलते रहेंगे।

अरावली कोई साधारण पर्वत श्रृंखला नहीं है। यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, जिसकी उम्र लगभग दो अरब वर्ष आंकी जाती है। दिल्ली से गुजरात तक लगभग 650 किलोमीटर में फैली यह श्रृंखला उत्तर भारत के पर्यावरणीय संतुलन की रीढ़ रही है। यह थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर फैलाव को रोकने वाली एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है और गंगा के मैदानों को मरुस्थलीकरण से बचाती है। इसकी चट्टानें, वनस्पतियां और घाटियां भूजल को संरक्षित करने में मदद करती हैं। चंबल, साबरमती और लूनी जैसी नदियों का उद्गम भी इसी क्षेत्र से होता है। इसके जंगल अनेक वन्य प्रजातियों को आश्रय देते हैं और जलवायु को स्थिर रखने में योगदान करते हैं। इस दृष्टि से अरावली केवल भूगोल नहीं, बल्कि जीवन तंत्र है, जिसकी क्षति का प्रभाव दूरदराज के क्षेत्रों तक महसूस किया जाता है।

अरावली कई दशकों से मानवीय दबाव झेल रही है। पत्थर, रेत और खनिज की बढ़ती मांग ने इसे खनन का प्रमुख केंद्र बना दिया है। पत्थर और चूना-पत्थर की निरंतर निकासी ने कई पहाड़ियों को कमजोर कर दिया है। जंगलों का नुकसान हुआ है। आसपास के शहरों में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती गई है। भूजल स्तर नीचे गया और ग्रामीण आबादी को पानी के लिए टैंकरों तथा अस्थायी साधनों पर निर्भर होना पड़ा। कई बार नियम बनाए गए, कई बार न्यायालय का सीधा हस्तक्षेप हुआ। मगर इनका पालन हमेशा ठोस रूप में नहीं हो सका।

इसी पृष्ठभूमि में सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2024 में नए खनन पट्टों और पुराने पट्टों के नवीनीकरण पर रोक लगाई और एक विशेषज्ञ समिति से विस्तृत रपट मांगी। समिति ने इस बात पर बल दिया कि अब तक खनन परियोजनाओं का मूल्यांकन प्रायः अलग-अलग किया गया, जबकि उनका संयुक्त प्रभाव पूरे क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर पड़ता रहा है। इसलिए समिति ने संचयी पर्यावरणीय प्रभाव के वैज्ञानिक अध्ययन, सटीक नक्शानवीसी, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, वन्यजीव गलियारों की सुरक्षा और पत्थर क्रशर इकाइयों पर सख्त निगरानी जैसी सिफारिशें कीं।

दिल्ली से गुजरात तक लगभग 650 किलोमीटर में फैली अरावली श्रृंखला उत्तर भारत के पर्यावरणीय संतुलन की रीढ़ रही है। यह थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर फैलाव को रोकने वाली एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है और गंगा के मैदानों को मरुस्थलीकरण से बचाती है। इसकी चट्टानें, वनस्पतियां और घाटियां भूजल को संरक्षित करने में मदद करती हैं। चंबल, साबरमती और लूनी जैसी नदियों का उद्गम भी इसी क्षेत्र से होता है। इसके जंगल अनेक वन्य प्रजातियों को आश्रय देते हैं और जलवायु को स्थिर रखने में योगदान करते हैं। इस दृष्टि से अरावली केवल भूगोल नहीं, बल्कि जीवन तंत्र है, जिसकी क्षति का प्रभाव दूरदराज के क्षेत्रों तक महसूस किया जाता है।

इसी क्रम में अरावली की वैज्ञानिक परिभाषा तय करने का प्रश्न उभरा। अलग-अलग राज्यों तथा संस्थानों द्वारा अरावली की पहचान के लिए भिन्न-भिन्न मानदंड अपनाए जाते रहे हैं। इस असंगति के कारण कई क्षेत्रों में यह विवाद बना रहा कि कौन-सा इलाका वास्तव में अरावली का हिस्सा है। इस भ्रम का लाभ उठा कर खनन को वैध ठहराने की कोशिशें भी होती रहीं। इसे समाप्त करने के लिए बनाई गई संयुक्त समिति ने सुझाव दिया कि जो पहाड़ियां सौ मीटर से अधिक ऊंचाई रखती हैं, उन्हें अरावली की परिधि में माना जाए। न्यायालय ने इस मानक को स्वीकार किया, लेकिन यहीं से व्यापक असहमति और विरोध शुरू हुआ।

पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रहे विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली जैसी अत्यंत पुरानी और घिस कर बनी पर्वतमाला को केवल ऊंचाई के आधार पर परिभाषित करना उसके वास्तविक महत्त्व को कम करके देखना होगा। इस श्रृंखला की कई पहाड़ियां अपेक्षाकृत नीची अवश्य हैं, परंतु वे वर्षा जल को रोकने, भूजल पुनर्भरण और जैव विविधता बनाए रखने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि केवल सौ मीटर की सीमा लागू कर दी जाए, तो बड़ी संख्या में ऐसी पहाड़ियां अरावली की परिभाषा से बाहर हो सकती हैं और उन पर खनन के लिए कानूनी रास्ते खुल सकते हैं। यही वह मुख्य चिंता है जिसे अब न्यायालय ने गंभीरता से लिया है और इसी कारण उसने पूर्व सिफारिशों और टिप्पणियों को अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया है।

सरकार की ओर से यह कहा गया कि आदेशों और प्रक्रियाओं को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। जबकि न्यायालय ने साफ किया है कि जब तक नई उच्च स्तरीय समिति स्वतंत्र रूप से पूरी प्रक्रिया की समीक्षा नहीं कर लेती, तब तक न तो सौ मीटर वाली परिभाषा लागू होगी और न ही उससे जुड़े अन्य निर्देश प्रभावी होंगे। इस प्रकार न्यायालय ने संरक्षण तथा नीति निर्माण दोनों को और अधिक वैज्ञानिक तथा पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है। राज्य सरकारों की चिंताएं भी स्वाभाविक हैं। अरावली चार राज्यों में फैली हुई है और हर राज्य की अपनी भूमि नीति, राजस्व संरचना और प्रशासनिक सीमाएं हैं। खनन कई राज्यों के लिए राजस्व का महत्त्वपूर्ण स्रोत रहा है।

इसी संदर्भ में 'अरावली ग्रीन वाल' परियोजना का उल्लेख भी आवश्यक है। इस योजना में अरावली के आसपास बंजर भूमि को पुनर्जीवित कर हरियाली बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। दावा किया गया है कि इससे मरुस्थलीकरण पर रोक लगेगी और स्थानीय पर्यावरण सुदृढ़ होगा। मगर कई स्थानीय समुदायों को आशंका है कि इस योजना से भूमि उपयोग पर नए प्रतिबंध लग सकते हैं और पारंपरिक चराई, खेती और बसावट प्रभावित हो सकती है। इसलिए जो भी हो, स्थानीय समुदायों की सहमति और सक्रिय भागीदारी के साथ किया जाए। अरावली पर प्रश्न यह भी है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए?

सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम निर्णय इस दिशा में पुनर्विचार का अवसर है। इससे यह उम्मीद जन्म लेती है कि अरावली की रक्षा पर होने वाली बहस अब अधिक गहराई, वैज्ञानिकता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ेगी। यदि नई समिति निष्पक्षता से सभी पक्षों की बात सुन कर संतुलित सिफारिशें करती है और सरकारें उन्हें ईमानदारी से लागू करती है, तो आज का विवाद कल के विश्वास में बदल सकता है। यदि प्रक्रिया फिर से केवल कागजों में सीमित रह गई और व्यवहार में वही पुरानी कमजोरियां कायम रहीं, तो अरावली की प्राचीन पहाड़ियां एक बार फिर विकास की कीमत चुकाने को मजबूर होंगी। यही आशंका आज की बहस का मूल कारण है और यही वजह है कि सब कुछ ठीक दिखने के बावजूद असहमति की आवाज थम नहीं रही है।

आवश्यक है अरावली को बचाना

हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा के संदर्भ में दिए गए अपने ही फैसले पर रोक लगा दी। उस फैसले में सौ मीटर ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली मानने को मंजूरी दे दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप कई छोटी, लेकिन पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण भू-आकृतियां संरक्षण की कानूनी सुरक्षा से बाहर आ सकती थीं। इस पर पर्यावरणीय विरोध और कानूनी प्रश्न उठे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि उसे लागू करने से पहले उसकी वैज्ञानिक, पर्यावरणीय और कानूनी समीक्षा आवश्यक है।

अदालत ने विशेषज्ञ समिति के गठन का प्रस्ताव रखा है, ताकि परिभाषा, खनन नियम, संरक्षित क्षेत्र और पारिस्थितिकीय निरंतरता से जुड़े सभी मुद्दों का विस्तृत अध्ययन हो सके। नवीनतम निर्णय इसका संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी मानता है कि पहले के निर्णय के वैज्ञानिक और पारिस्थितिकीय परिणाम संदेहास्पद हैं। 20 नवंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की एकसमान परिभाषा को स्वीकृति देने वाला आदेश एक लंबे समय से प्रशासनिक स्पष्टता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। यह आदेश भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला की कानूनी और पारिस्थितिकीय सुरक्षा को कमजोर कर सकता था, खासकर तब, जब वह पहले से ही अभूतपूर्व दबाव में है।

अरावली करीब दो अरब वर्ष पुरानी भू-वैज्ञानिक प्रणाली है, जो भूजल भरण को नियंत्रित करती है, मरुस्थलीकरण को रोकती है, जलवायु को संतुलित करती है और उत्तर-पश्चिम भारत में लाखों लोगों की आजीविका का सहारा है। इसे केवल ऊंचाई आधारित नियम से परिभाषित करना न केवल वैज्ञानिक रूप से गलत था, बल्कि पारिस्थितिकीय रूप से भी खतरनाक था। जिस समिति की रिपोर्ट पर उक्त आदेश आधारित था, वही समिति स्वीकार करती है कि अरावली परिदृश्य में ढलान और ऊंचाई व्यापक रूप से बदलती रहती है। समिति के अनुसार 34 में से 23 अरावली जिलों में औसत ढलान छह डिग्री से कम है, जबकि 12 जिलों में यह तीन डिग्री से भी कम है। रिपोर्ट यह सही निष्कर्ष निकालती थी कि केवल ढाल और

डा. लक्ष्मीकांत शर्मा

अरावली को ऊंचाई से परिभाषित करना न केवल वैज्ञानिक रूप से गलत, बल्कि पारिस्थितिक रूप से खतरनाक भी था

पारिस्थितिकीय संतुलन में महत्वपूर्ण है अरावली। फाइल

ऊंचाई को मानदंड बनाना विसंगति बढ़ाएगा। इसके बावजूद अंतिम सिफारिश में 100 मीटर के प्रविधान को मान्यता दे दी गई थी। यह वैज्ञानिक तर्क और प्रशासनिक विवेक के मूल सिद्धांतों के विपरीत था। भारतीय भू-आकृतिक परिस्थितियों में 100 मीटर ऊंचाई का नियम मनमाना था। अरावली जिलों में औसत ऊंचाई कुछ क्षेत्रों में 100–200 मीटर से लेकर केवल एक जिले में 600 मीटर से अधिक है। इतनी विविधता में एकसमान सीमा लागू करना, भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और सर्वे आफ इंडिया के सिद्धांतों के विपरीत है।

इसी प्रकार 500 मीटर 'रेंज कनेक्टिविटी नियम' भी चिंताजनक था। इसके अनुसार दो या अधिक पहाड़ियां यदि 500 मीटर के भीतर हों तो उन्हें एक अरावली रेंज माना जाएगा। इसका कोई भू-वैज्ञानिक आधार नहीं और न ही भारतीय पर्वत प्रणाली मानचित्रण में कोई उदाहरण। सबसे अधिक चिंता का विषय यह था कि समिति ने अरावली क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों के खनन की अनुमति का प्रविधान सुझाया था। यह सबसे नाजुक कोर क्षेत्रों में खनन के लिए कानूनी दरवाजा खोल देता।

अरावली कम नाजुक नहीं, बल्कि अधिक नाजुक है। अरावली राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में फैली है। इसकी चट्टानें पुरानी और भंगुर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को बार-बार मरुस्थलीकरण के विरुद्ध एक पारिस्थितिकीय ढाल के रूप में मान्यता दी है। कोई भी परिभाषा जो इस सुरक्षा सीमा को कम करे, वह विज्ञान और न्यायिक परंपरा दोनों के विरुद्ध है। अरावली एक प्राचीन भू-वैज्ञानिक, जल-चक्र और पारिस्थितिकीय प्रणाली है, जो उत्तर-पश्चिम भारत में जलस्रोत, मरुस्थलीकरण नियंत्रण और स्थानीय जीवन को बनाए रखती है। अरावली संकट का समाधान अल्पकालिक प्रशासनिक कदमों से नहीं होगा। इसके लिए स्थायी, विज्ञान-आधारित समाधान आवश्यक हैं। पर्यावरणविद् एक राष्ट्रीय अरावली विकास प्राधिकरण की स्थापना की वकालत करते रहे हैं। पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे रिज टाप, वनाच्छादित पहाड़ियां और वन्यजीव कारिडोर में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, किसी भी प्रकार की सार्वभौमिक छूट के बिना, क्योंकि एक बार यदि अरावली का खनन हो गया तो उसे कभी पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। अरावली को स्थायी कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए, चाहे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में मिले या फिर भारत की प्राचीन पर्वत विरासत प्रणाली के रूप में एक नई कानूनी श्रेणी बनाकर।

अरावली केवल ऊंचाई से परिभाषित नहीं हो सकती। यह एक भू-वैज्ञानिक, जलवैज्ञानिक और पारिस्थितिकीय प्रणाली है, जो उत्तर-पश्चिम भारत को संभालती है। यदि हम इसकी परिभाषा कमजोर कर देंगे, तो कल इसकी सुरक्षा भी कमजोर हो जाएगी और जब तक हमें इसका नुकसान दिखाई देगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्णय ने इस बहस को वैज्ञानिक, भू-वैज्ञानिक और पारिस्थितिकीय संदर्भ में आगे ले जाने का अवसर दिया है और इसे प्रशासनिक उत्तरदायित्व और न्यायिक विवेक के साथ पुनर्मूल्यांकन करने का संकेत दिया है।

(लेखक राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं अरावली पर्वतमाला के शोधकर्ता हैं)
response@jagran.com

कमजोर कड़ियों से मुक्ति आवश्यक

ए. सूर्यप्रकाश

पीएम मोदी को इस साल केंद्रीय मंत्रिमंडल की संरचना और उन लोगों के संबंध में कुछ कड़े निर्णय करने होंगे, जो भाजपा शासित राज्यों में सरकार चला रहे हैं

नए साल में कुछ नई चुनौतियां भी साथ आई हैं। देश और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी को इन चुनौतियों का सामना करना है। स्वाभाविक रूप से ऐसी चुनौतियों के कुछ तार कहीं न कहीं पिछले साल से भी जुड़े हुए हैं। अस्थिरता के शिकार वैश्विक ढांचे में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने जो अनिश्चितता बढ़ाई, उससे उपजी चुनौतियों को प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता से संभाला। हालांकि इंडिगो संकट, अरावली खनन, प्रदूषण से कराहती राष्ट्रीय राजधानी के मुद्दे परेशान करने वाले रहे। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे पूर्व विधायक को मिली राहत जैसी घटना भी चौंकाने वाली रही। हालांकि बाद में शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग की घटना में जिंदा जले लोग भी राज्य सरकार की अक्षमता और भ्रष्टाचार के शिकार बने। यह भी एक दुर्योग रहा कि ऐसे सभी मामले साल की अंतिम तिमाही के दौरान सामने आए, जो कहां न कहीं दर्शाता है कि प्रधानमंत्री के पास न केवल केंद्रीय, बल्कि राज्यों के स्तर पर भी सक्षम मंत्रियों एवं नौकरशाहों का अभाव है, जो एक पारदर्शी एवं प्रभावी सरकार की योजनाओं को लागू करने में सहायक बन सकें।

इंडिगो प्रकरण की ही बात करें तो विमानन नियामक ने इस कंपनी को ऐसी गुंजाइश ही क्यों दी कि वह बाजार के 65 प्रतिशत हिस्से पर काबिज हो सके। उसे परिचालन विस्तार के लिए ऐसी अनुमति कैसे मिलती गई कि वह नियामक को ही अपनी अंगुलियों पर नचा सके? ऐसे में डीजीसीए के ढांचे और कार्यप्रणाली पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। क्या उसके अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं या महज उसमें नियुक्ति पाने वाले नौकरशाह ही हैं। दिसंबर की शुरुआत में विमान सेवाओं के एक बड़े हिस्से के लगभग ठप पड़ने के कई सप्ताह बाद भी इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं।

जहां तक अरावली मुद्दे का सवाल है तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस मामले में नवंबर में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बचाव किया। हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ही अपने उस फैसले पर स्थगन का निर्णय किया। नवंबर में अदालत ने सरकार द्वारा गठित 'विशेषज्ञ पैनल'' द्वारा दी गई एक अजीब परिभाषा को स्वीकार कर लिया था। इसमें अरावली पहाड़ियों को 100 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया था। जहां

अवधेश राजपूत

मंत्रालय ने अपनी तथाकथित ''विशेषज्ञ समिति'' की इस राय का जोरदार बचाव किया, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने नवीनतम आदेश में इसके विपरीत रुख अपनाया। सरकार की 'विशेषज्ञ समिति' की बात करें तो उसमें अधिकांश सदस्य पर्यावरण विशेषज्ञ न होकर नौकरशाह ही थे। इस मामले को लेकर रुख बदलने में मीडिया के सवालों की अहम भूमिका रही है। मीडिया के माध्यम से ही यह हैरान करने वाली जानकारी भी सामने आई कि नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सरकार ने दर्जनों खनन पट्टों को त्वरित गति से स्वीकृति प्रदान की। यदि यह सच है तो एक बड़ी विडंबना को ही दर्शाता है कि खनन माफिया पूरे परिदृश्य को किस हद तक प्रभावित करने की स्थिति में पहुंच गया है। सरकार इस मामले में समय से स्पष्टता नहीं दिखा सकी, जिससे उसकी छवि प्रभावित हुई।

यह किसी से छिपा नहीं रह गया है कि राजधानी दिल्ली प्रदूषण के मामले में नए कीर्तिमान बनाती जा रही है, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय के पास इस स्थिति को परिवर्तित करने के लिहाज से कुछ उल्लेखनीय नहीं है। बीते साल कुछ दिनों के दौरान एक्यूआइ का आंकड़ा 500 से 1,000 तक पहुंचता दिखा, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय ने किसी निदान के बजाय दोषारोपण का सहारा लेने को ही प्राथमिकता दी। कभी पराली को लेकर अंगुली उठाई गई तो कभी आम आदमी पार्टी पर। प्रदूषण से निपटने में किसी कारगर कार्ययोजना के मामले में दिल्ली सरकार भी अकर्मण्य ही नजर आई। इसका ही परिणाम है कि दिल्ली रहने के लिहाज से बेहद खतरनाक शहर बन गया है। लोग असहाय महसूस कर रहे हैं। इससे केंद्र सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है।

गुजरे हुए साल के अंतिम दिनों में उन्नाव दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत भी चर्चा के केंद्र में रही। सीबीआइ की ओर से पेश हुए सालिसिटर जनरल ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को पलट भी दिया। कुछ वर्ष पूर्व यह मामला सामने आने के बाद सेंगर को भाजपा ने निष्कासित कर दिया था, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ऐसे व्यक्ति को पहले-पहल भाजपा में शामिल ही क्यों किया गया? इस पूरे मामले में कई कानूनी सवाल भी उठते हैं, क्योंकि पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी सेंगर जेल में बंद है। सेंगर पर सख्ती के मामले में भी मीडिया के रुख की अहम भूमिका रही।

गोवा का नाइट क्लब भी शासन-प्रशासन के स्तर पर घोर लापरवाही का ज्वलंत उदाहरण रहा। क्लब में लगी आग में 25 लोग मारे गए और कई घायल हुए। कई आवश्यक स्वीकृतियों के बिना भी इस क्लब का संचालन हो रहा था। इसका प्रवेश और निकास मार्ग ही इतना संकरा था कि राहत एवं बचाव अभियान में तमाम बाधाएं आईं। क्या यह सब पहले नहीं दिख रहा था? ऐसे में, सवाल उठना स्वाभाविक है कि किसकी कृपा से क्लब को लाइसेंस मिला और वहां जिम्मेदार लोगों ने सुरक्षा प्रबंधों की सुध लेने की जिम्मेदारी क्यों नहीं समझी। इस परिदृश्य को देखते हुए यह कहना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री के लिए कुछ कड़े निर्णय लेने का समय आ गया है। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की संरचना से लेकर उन लोगों के संबंध में कुछ कड़े निर्णय करने होंगे, जो भाजपा शासित राज्यों में सरकार चला रहे हैं। अन्यथा अप्रिय घटनाएं उनकी छवि पर नकारात्मक असर डालेंगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए उन्हें अविलंब कड़ा रुख अपनाना होगा।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

लाओत्से की अंतिम सीख

मरते समय किसी ने लाओत्से से पूछा, आप अपने जीवन के कुछ रहस्य बता दें। लाओत्से ने कहा, पहला रहस्य तो यही है कि मुझे जिंदगी में कोई कभी हरा नहीं सका। उनके शिष्य बड़े उत्सुक हो गए। उन्होंने कहा, यह तो आपने हमें कभी बताया नहीं। जीतना तो हम भी चाहते हैं। हमें तरकीब बताइए?

लाओत्से ने कहा, तुम सब भूल कर गए। मैंने कुछ और कहा था। मैंने कहा था, मुझे कोई हरा नहीं सका, और तुम लोग पूछते हो कि जीतना तो हमें भी है। ये दोनों बातें उल्टी हैं। ये एक सी लगती हैं। शब्दों की दुनिया में इनका एक ही अर्थ है कि जो नहीं हारा, मतलब जीता। तुम सब मेरी बात न समझ सकोगे।

शिष्यों ने कहा, हमें समझाएं। वह तरकीब तो बता दें कि आप कैसे नहीं हारे? लाओत्से ने कहा, मुझे कोई हरा न सका, क्योंकि मैं सदा हारा हुआ था। मुझे कोई हरा न सका, क्योंकि मैंने कभी जीतना ही नहीं चाहा। असल में, मेरी लड़ाई ही खड़ी न हो सकी। मुझसे कोई लड़ने भी आया, तो मैं हारा ही हुआ था। हराने में तो उसी को मजा आता है, जो जीतना चाहता हो। जो जीतना ही नहीं चाहता, उसको हराने में क्या मजा आएगा? लाओत्से ने आगे कहा, तुम लोग दूसरी बात पूछ रहे हो। तुम पूछ रहे हो कि ऐसी कोई तरकीब बताएं, जिससे कि हम जीत जाएं। अगर तुमने जीतने की सोची, तो तुम हारोगे। जीतने की सोचने वाला हारता ही है।

लाओत्से ने आगे कहा, मेरा कभी कोई अपमान नहीं कर सका। तब एक शिष्य ने कहा, इसका भी राज बताइए, क्योंकि अपमान तो हमें भी बहुत तकलीफ देता है। लाओत्से ने उससे कहा, फिर तुमसे भूल हो रही है। है। मेरा कोई अपमान नहीं कर सका, क्योंकि मैंने मान को कोई आकांक्षा नहीं पाली। तुम्हारा अपमान होता ही रहेगा, क्योंकि तुम मान की आकांक्षा से भरे हो।

लाओत्से कहता है, जीवन का राज घास से पूछो, जिनको बड़ी से बड़ी आंधी भी उखाड़ नहीं पाती। क्या है उनका राज? वे पूरे के पूरे सुरक्षित रह जाते हैं। वे इतने कमजोर हैं कि जरा सा झोंका हवा का उन्हें तोड़ दे, पर भयंकर झंझावात चलता है और उनकी जड़ें भी नहीं हिलतीं। बड़े-बड़े वृक्ष, जिनकी गहरी जड़ें हैं जमीन में,

मुझे कोई हरा न सका, क्योंकि मैं सदा हारा हुआ था। मुझे कोई हरा न सका, क्योंकि मैंने कभी जीतना ही नहीं चाहा। जो जीतना ही नहीं चाहता, उसको हराने में क्या मजा आएगा?

वे धराशायी हो जाते हैं।

पूछो, उन बड़े वृक्षों की भूल क्या थी? उन वृक्षों ने लड़ना चाहा, जीतना चाहा। बड़े वृक्षों ने झंझावात से युद्ध मोल लिया। उन्होंने कहा, हम कुछ हैं। वहीं घास के तिनके चुपचाप झुक गए। उन्होंने कोई झगड़ा ही न लिया। उन्होंने झंझावात को दुश्मन ही न माना। उन्होंने उसे प्रेम से अंगीकार कर लिया। उन्होंने उसे खेल समझा, युद्ध नहीं समझा। उन्होंने कहा- ठीक है, बह जाओ और रास्ता दे दिया।

ओशो

रोजगार गारंटी को मजबूत बनाए रखने की जरूरत

यहां स्कैन करें

हिमांशु | एसोशिएट प्रोफेसर, जेएनयू

सरकार ने दो दशक पुराने 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (मनरेगा) का नाम और उद्देश्यों को बदलकर उसकी जगह 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' या वीबी-जी राम जी कानून लागू किया है।

सार्वजनिक रोजगार योजनाएं लंबे समय से देश में आजीविका सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के लिए लागू की जाती रही हैं। महाराष्ट्र में 1970 के दशक से ऐसी ही योजना प्रभावी है। हालांकि, मनरेगा में अलग बात यह थी कि इसमें हरेक ग्रामीण परिवार को मांग-आधारित और बिना शर्त रोजगार की गारंटी दी गई थी। बेशक, इसमें रोजगार की पूर्ण गारंटी नहीं थी, क्योंकि इसमें एक परिवार को अधिकतम 100 दिनों का ही रोजगार मुहैया कराने का प्रावधान था, लेकिन इसने ग्रामीण बुनियादी ढांचों में सुधार, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी उपयोगिता तब विशेष रूप से साबित हुई, जब कोरोना महामारी के दौरान गांव लौटे लाखों प्रवासियों के लिए भी यह कानून जीवनदायक बना।

मनरेगा की खासियत यह भी थी कि इसे कानूनी समर्थन हासिल था। इसकी बिना शर्त सबके लिए उपलब्धता ने इसे अनेक परिवारों की जीवन-रेखा बना दिया। जब पश्चिम बंगाल सरकार ने इसको रोकने की कोशिश की, तब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मनरेगा को महज तकनीकी कारणों से नहीं रोका जा सकता। मजदूरों के लिए मनरेगा से इतर कहीं और काम करने का मतलब था, मनरेगा में तय मजदूरी से अधिक मिलना। इस तरह इस कानून ने श्रम बाजार को परोक्ष रूप से मजबूत किया। इस बात के पर्याप्त सुबूत हैं कि इसने 2004-05 से 2011-12 तक ग्रामीण मजदूरी बढ़ाने और गरीबी कम करने में मदद की। बाद के वर्षों में इसके कई प्रावधानों को केंद्र एवं राज्य सरकारों ने कमजोर किया और इसकी मजदूरी, जो बाजार दर से अधिक थी, वह उसकी दो-तिहाई रह गई। फिर भी, इसमें काम की मांग बनी हुई थी, जिसका फायदा अमूमन औरतें और वंचित समुदायों के लोग उठा रहे थे।

काम की पूरी गारंटी न रहने से ग्रामीण संकट बढ़ सकता है और धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुस्त पड़ सकती है।

नए कानून में मनरेगा वाले अधिकार का अभाव है और अधिकतम सीमा से अधिक काम की मांग नहीं की जा सकती। इसके तहत अब केंद्र सरकार अपने तय 'उद्देश्यों' के तहत फंडिंग करेगी। कृषि सीजन में इस कानून के तहत काम मांगने की गारंटी 60 दिनों के लिए टाल दी गई है। बेशक, इस दौरान अधिकतर मजदूर मनरेगा का काम नहीं ढूंढ़ते थे, पर गारंटी के कारण उन्हें बेहतर मजदूरी के लिए मोलभाव करने में मदद मिलती थी। मनरेगा ने निस्संदेह मजदूरी बढ़ाने में मदद की, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि इसने सूखा या खेती के काम की कमी के दौरान रोजगार उपलब्ध कराकर मजदूरों को सहारा दिया। हालांकि, हाल के दिनों में 22 राज्यों में इसकी मजदूरी दर बाजार दर से कम हो गई थी, जिस कारण इसमें काम की मांग घट गई थी। मगर ऐसे समय में, जब खेती की मजदूरी स्थिर है और गैर-खेती की मजदूरी में करीब एक दशक से कमी आ रही है, तब फसल सीजन के दौरान इसे लागू करने पर रोक लगाने से मजदूरी पर और दबाव पड़ सकता है। इसके अलावा काम के अधिकतम दिनों को 125 करने का भी कोई खास फायदा नहीं मिल सकता, क्योंकि पिछले दो दशकों में मनरेगा में काम के दिनों की औसत संख्या प्रति परिवार 50 से कम रही है और मुश्किल से दो से तीन प्रतिशत परिवार ही 100 दिनों तक काम कर पाए हैं।

नए कानून को आर्थिक मोर्चे पर भी जूझना पड़ सकता है। मनरेगा में 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब वह बड़े राज्यों को खर्च का सिर्फ 60 प्रतिशत हिस्सा देगी। इस तरह, नया कानून कमजोर अर्थव्यवस्था वाले राज्यों के लिए बोझ बन सकता है। इससे राज्यों के बीच असमानता बढ़ सकती है, जिससे कम उत्पादकता और प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को नुकसान हो सकता है। मनरेगा ज्यादातर गरीबों के लिए एकमात्र सामाजिक सुरक्षा की गारंटी थी, जिससे लगभग एक-तिहाई ग्रामीण परिवार लाभ उठा रहे थे। जाहिर है, इसके खत्म होने से ग्रामीण संकट बढ़ सकता है और धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुस्त पड़ सकती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

भारतीय विदेश नीति पर रहेगी नजर

यहां स्कैन करें

हर्षवर्धन श्रृंगला | पूर्व विदेश सचिव व सांसद

नए साल में हमारा फोकस 'भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे' पर होगा, जो परिवहन, ऊर्जा व डिजिटल नेटवर्क के जरिये इन देशों से हमारे रिश्ते मजबूत करेगा।

हम नए साल में प्रवेश कर गए हैं। इस समय दुनिया में अनिश्चितता, शक्ति संतुलन में बदलाव और बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति बनी हुई है। साल के पहले दिन ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ताइवान संबंधी बयान ने स्पष्ट कर दिया कि यह वर्ष काफी जटिल स्थितियां जनने जा रहा है। जिनपिंग का दो टूक लहजे में यह कहना कि ताइवान का चीन में विलय होकर रहेगा और ताइवानी राष्ट्रपति का अपनी संप्रभुता से किसी किस्म का समझौता करने से इनकार करना साल 2026 में टकराव की आशंकाओं की एक बानगी भर है। ऐसे माहौल में भारत की विदेश नीति पर सबकी निगाह रहने वाली है।

हालांकि, अपने उद्देश्य की स्पष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय-वैश्विक हितों को साधने वाली साझेदारियों के प्रति हमारी नीति पूरी तरह साफ है। इस साल अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आसियान, अफ्रीकी संघ और खाड़ी के देशों से रिश्ते हमारी विदेश नीति के केंद्र में रहेंगे। भारत-अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी, खासकर रक्षा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्थिर रहने की उम्मीद है। अमेरिका के साथ व्यापार और टैरिफ पर जारी मतभेदों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मित्रता और ट्रंप के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किए जाने से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की संभावना है। अमेरिका ने अपनी 'राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025' में भारत के साथ वाणिज्यिक संबंधों और हिंद-प्रशांत रणनीतिक संबंधों को एक साथ विकसित करने के प्रति भी रुचि जताई है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन दिनों रूस से बाहर कम यात्रा करते हैं। इसके बावजूद बीते दिसंबर में उनकी भारत यात्रा हुई। यह अपवाद था। उस यात्रा ने भारत के साथ रूस के संबंधों की अहमियत को एक बार फिर रेखांकित किया। यूरेशियाई आर्थिक संघ के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते के तहत रूस से व्यापारिक रिश्ते को विस्तार देने पर इस साल फोकस रहेगा।

चीन के साथ संबंधों में कुछ विवादों और सीमा-संघर्ष के कारण गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। बढ़ते व्यापार घाटे के अलावा दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में उसके बढ़ते कदमों के कारण भी कई चुनौतियां पैदा हुई हैं, फिर भी उसके साथ रिश्ते सामान्य बनाने की दिशा में इस वर्ष नई कोशिशें हो सकती हैं। ब्रिटेन और ओमान के साथ तरजीही व्यापार समझौतों से भारतीय निर्यात, पूंजी निवेश और भारतीय युवाओं के लिए वैश्विक आवागमन के द्वार खुलने के संकेत हैं। इसी तरह, गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय नेताओं की भारत यात्रा और यूरोपीय संघ के साथ लंबे समय से प्रतीक्षित आर्थिक समझौते को संपन्न कराने की दिशा में उठाए गए कदमों से यूरोपीय संघ के साथ हमारा जुड़ाव बढ़ेगा।

भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण कारक 'कनेक्टिविटी' रहा है। इससे आर्थिक एकीकरण और रणनीतिक साझेदारियों में घनिष्ठता आती है। इस साल हमारा ध्यान 'भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे' (आईएमईसी) पर केंद्रित होगा, जो एकीकृत परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल नेटवर्क के जरिये इन देशों के साथ हमारे संबंधों को काफी मजबूत कर सकता है। इसके लागू होने से व्यापारिक कुशलता बढ़ेगी, आपूर्ति-श्रृंखला मजबूत हो सकेगी और भारत उभरती क्षेत्रीय मुहिम में अहम भूमिका निभा सकता है। पश्चिम एशिया से शुरू होने वाली 'लुक वेस्ट' नीति सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ओमान समेत खाड़ी के अन्य देशों व इजरायल के साथ भारत के संबंधों को और मजबूती देगी।

आसियान के साथ भारत का जुड़ाव उसकी 'एक्ट ईस्ट' नीति का मुख्य स्तंभ बना रहेगा, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, आर्थिक एकीकरण और समुद्री सुरक्षा के साझा हितों पर आधारित है। सहयोग के क्षेत्र में व्यापार व निवेश, आपूर्ति-श्रृंखला की मजबूती, डिजिटल कनेक्टिविटी और क्षमता-निर्माण भी शामिल हैं। 'भारत-अफ्रीका फोरम' के आयोजन से अफ्रीकी संघ के साथ भारत की साझेदारी को इस साल नई ऊर्जा मिलेगी। यह दशकों के विकास सहयोग और 'दक्षिण-दक्षिण एकता' पर आधारित है। क्षमता निर्माण, विकास, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल सार्वजनिक ढांचा और कनेक्टिविटी के मामले में सहयोग के अतिरिक्त शांति व सुरक्षा के साथ बढ़ता व्यापार-निवेश इस साझेदारी का अभिन्न अंग बना रहेगा।

भारत के निकट पड़ोस में घट रही घटनाओं को कम करके नहीं आंका जा सकता, इसलिए भारत 'पड़ोस पहले' की अपनी नीति को इस साल भी प्राथमिकता देना जारी रखेगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि भूटान में पनबिजली परियोजनाओं से लेकर नेपाल में सड़क व बुनियादी ढांचा निर्माण की पहल के साथ-साथ श्रीलंका व मालदीव से समुद्री व रक्षा सहयोग ने एक क्षेत्रीय भागीदार के रूप में हमारी स्थिति को मजबूत बनाया है। भारत बांग्लादेश में हो रहे राजनीतिक और संस्थागत बदलाव से तालमेल बिठा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में विदेश मंत्री एस जयशंकर का शरीक होना इसका ठोस प्रमाण है। भारत नेपाल के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और गहरा कर रहा है, तो भूटान के प्रमुख रणनीतिक भागीदार के रूप में अपनी भूमिका को मजबूती दे रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्रवाई करने के प्रयासों ने भारत की स्थिति एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में मजबूत बनाई है।

जाहिर है, *वसुधैव कुटुंबकम* के सिद्धांत के तहत दुनिया के गरीब देशों में कल्याणकारी कार्यों में योगदान भारतीय विदेश नीति का अहम पहलू है। भारत 'ग्लोबल साउथ' की एक प्रमुख आवाज के रूप में उभरा है। भारत इस क्षेत्र की विकास प्राथमिकताओं, न्यायसंगत विकास और वैश्विक संस्थानों में विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की वकालत करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन के नेताओं के साथ सीधे संपर्क में हैं। उन्होंने जी-20 और संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े वैश्विक मंचों पर भी इस संघर्ष को समाप्त कराने में संवाद का समर्थन किया है। इस तरह से वह कूटनीतिक तौर पर सभी पक्षों से जुड़े हैं। ये तमाम कवायदें भारत के इस विश्वास को पुष्ट करती हैं कि संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही शांति संभव है। साल 2026 में हमारा कदम सतर्क, संतुलित और आशावादी रहेगा। इस तरह, बहुध्रुवीय दुनिया में हमारी विदेश नीति के केंद्र में रणनीतिक स्वायत्तता, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास ही रहेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

EDU TERIA